LKS
WWW.LKSTV.IN
दैनिक लोकतंत्र की शान
दिल्ली से प्रकाशित
गुरुवार 11 जून 2026
लोकतंत्र का स्तंभ

प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी बधाई, दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया

एजेंसी। नई दिल्ली

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रस्ताव पारित कर 10 जून को भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव बताया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। प्रस्ताव के अनुसार "नरेन्द्र मोदी ने 4,399 दिनों की निरंतर सेवा पूरी कर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मंत्रिमंडल ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, जनभागीदारी और जनता के विश्वास का प्रतीक है। प्रस्ताव में उल्लेख किया गया कि यह अवसर ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने अपने 12 वर्ष पूरे किए हैं और वे लगभग 25 वर्षों की सतत शासन यात्रा के निकट पहुंच रहे हैं। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन को राष्ट्रसेवा और जनकल्याण के प्रति समर्पण का उदाहरण बताया गया। इसमें कहा गया कि "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र के साथ गरीबों के कल्याण को शासन के केंद्र में रखा गया। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवास, बिजली, स्वच्छ जल, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन तथा करोड़ों गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। युवाओं, महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण को भी प्रस्ताव में प्रमुखता से रेखांकित किया गया। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार, चंद्रयान मिशन, महिला आरक्षण, लखपति दीदी अभियान और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी पहलों का उल्लेख किया गया। प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नए आपराधिक कानूनों तथा श्रम सुधारों को महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, आत्मनिर्भर भारत, जी-20 की सफल अध्यक्षता तथा वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में रेखांकित किया गया। केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में कैबिनट के फैसलों और प्रस्ताव की जानकारी दी। उनके अनुसार पिछले 12 वर्षों की राजनीतिक स्थिरता, गतिशील शासन और दूरदर्शी नीतियों ने भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। इस बात को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरी कृतज्ञता और भविष्य के संकल्प को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को आधिकारिक तौर पर अपनाया।

जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटीः पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वह देश में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सुशासन और जनसेवा को अपना मूल मंत्र बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने विशेष संदेश में उन्होंने लिखा, जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जनविश्वास अर्जित करता है। इसके साथ ही उन्होंने शासन के प्राचीन आदर्शों को रेखांकित करते हुए एक संस्कृत सुभाषितम् भी साझा किया- सदानुरक्तप्रकृतिः प्रजापालनतत्परः। विनीतात्मा हि नृपतिर्भूयसी श्रियमश्नुते। इस श्लोक का गहरा अर्थ समझाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जनप्रतिनिधि सेवा को अपना परम धर्म मानकर निरंतर जनहित में कार्य करता है, सुशासन के माध्यम से जनता की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है तथा विनम्रता व संयम के साथ विकास को लक्ष्य बनाकर समाज की उन्नति के लिए समर्पित रहता है, वास्तव में वही जनविश्वास, यश और समृद्धि प्राप्त करता है। बता दें कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का यह लगातार तीसरा कार्यकाल है, जिसके दौरान उन्होंने 4,399 दिनों तक पद पर बने रहकर सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल का एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले यह बड़ी उपलब्धि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज थी। नेहरू जी के वर्ष 1952 से शुरू हुए कार्यकाल को ही इस गणना का आधार माना जाता है, क्योंकि देश में पहले आम चुनाव होने से पूर्व 1947 से 1952 के बीच की अवधि में वह अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर कार्यरत थे।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

10 करोड़ गरीब महिलाओं पर कुठाराघात

मोदी सरकार की सबसे बड़ी उज्ज्वला योजना जिसका प्रचार-प्रसार देश और विदेश तक मोदी सरकार ने किया था अब इस योजना में सरकार लगातार कटौती करती चली जा रही है। इसको लेकर मोदी सरकार के प्रति एक नई अवधारणा बनना शुरू हो गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है जिस योजना को सरकार अपनी सफलता के मानदंड में पिछले एक दशक से 10 करोड़ महिलाओं को सब्सिडी के गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कर रही थी इस योजना में 1 वर्ष में पहले 12 सिलेंडर देने की व्यवस्था थी उसे घटाकर 9 किया गया फिर 6 किया गया और अब सरकार ने चार सिलेंडर देने का निर्णय किया है। उज्जवला योजना के तहत 10 करोड़ गरीब महिलाओं का पंजीयन है। 642 रुपए प्रति सिलेंडर में इन्हें 14 किलो का सिलेंडर मिल रहा था जो अब 12 से घटकर चार पर आ गया है। सरकार इसमें 25000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को कम करने जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय-समय पर गरीब महिलाओं की आंखों में आंसू नहीं आएं इसके लिए उज्जवला योजना का प्रचार सारे देश में, हर चुनाव में करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में जब सरकार ने मनरेगा योजना को अभी बंद करके रखा है इसी बीच उज्ज्वला योजना के सिलेंडर घटा कर सबसे गरीब महिलाओं के ऊपर कुठाराघात किया है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर तीव्र कटाक्ष करते हुए सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का कहना है मोदी सरकार गरीबों का निवाला छिनती चली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वह पूंजीपतियों को लगातार राहत पहुंचा रही है। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल, पेट्रोल-डीजल और एलपीजी में जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है इसका लाभ कंपनियों को मिला है। उपभोक्ताओं से लगातार डीजल-पेट्रोल, एलपीजी के बड़े हुए दाम वसूल किये जा रहे हैं। अब तो हद हो गई है, पहले केंद्र सरकार ने मनरेगा को बंद किया, अब इसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत जो एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी के दाम पर 10 करोड़ गरीब महिलाओं को मिल रहे थे अब उन महिलाओं को आर्थिक संकट में इस सरकार ने डाल दिया है। कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है।

सरकार की आर्थिक स्थिति को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उसमें उज्ज्वला योजना के तहत यदि सरकार गरीब महिलाओं को नाराज कर सकती है तो यह भी कहा जा रहा है, सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बीच में सोना बेचने की भी खबर आई थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से सरकार की आर्थिक स्थिति को लेकर आए दिन नए-नए समाचार सुनने को मिल रहे हैं उसको देखते हुए अब सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। सरकार विभिन्न मामलों में जिस तरह से घिरी हुई है उसके बाद भी जब महंगाई, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही हो सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हों, ऐसे समय पर सरकार यदि इस तरह के निर्णय ले रही है तो इसका यही अर्थ निकाला जा रहा है कि भारत सरकार गहरे आर्थिक संकट में फस गई है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

आ रही नितिन नवीन की नई भाजपा टीम, मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल की तैयारी!

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संगठनात्मक ढांचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में एक नई और युवा टीम की घोषणा जल्द हो सकती है, वहीं मोदी कैबिनेट में भी नए चेहरों को जगह मिलने की अटकलें तेज हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, 15 जून के बाद कभी भी नए पदाधिकारियों के नामों का ऐलान हो सकता है, जबकि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। जनवरी में पदभार संभालने के बाद से ही 45 वर्षीय नितिन नवीन, जो भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, अपनी नई टीम के गठन में जुटे हैं। पार्टी की परंपरा रही है कि नए अध्यक्ष के चुने जाने के बाद संगठन में बदलाव होते हैं। पार्टी आलाकमान संगठन को अधिक युवा, अनुभवी और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला बनाना चाहता है। माना जा रहा है कि नई टीम में युवा और अनुभव का बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा, जिसमें आगामी राजनीतिक रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी और दलितों जैसे प्रमुख वर्गों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अध्यक्ष नवीन इन दिनों लगातार कई राज्यों का सघन दौरा कर जमीनी फीडबैक जुटा रहे हैं, जो संगठनात्मक बदलावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पार्टी संगठनात्मक बदलावों के साथ ही मोदी कैबिनेट में भी व्यापक फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे करने वाले हैं, जिसके बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें और तेज हो गई हैं।

मीनाक्षी नटराजन मामले में चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, नामांकन रद्द करने को बताया गलत

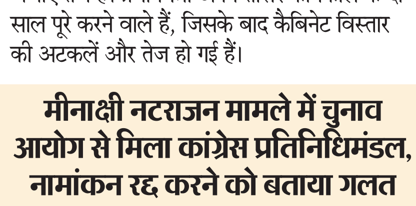

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को चुनाव आयोग से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल, पार्टी के विधि, सूचना का अधिकार (आरटीआई) एवं मानव संसाधन विभाग प्रमुख अभिषेक मनु सिंघवी, राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा, लोकसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला, महासचिव (संचार) जयराम रमेश, महासचिव दीपादास मुंशी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मीनाक्षी नटराजन शामिल थीं। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय पूरी तरह विकृत और कानूनी रूप से गलत है। नटराजन का नामांकन इस आधार पर निरस्त किया गया कि उन्होंने अपने फॉर्म में लंबित आपराधिक मामले का खुलासा नहीं किया। जबकि वास्तविकता यह है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। केवल एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें अदालत ने यह तय करना था कि संज्ञान लिया जाए या नहीं। चुनाव कानून की धारा 33ए में यह प्रावधान है कि केवल वही मामले उजागर करने होते हैं जिनमें अपराध साबित होने पर दो वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है और जिनमें आरोप तय हो चुके हों।

उरी सेक्टर में उपकरणों के रख-रखाव में ग्रेनेड फटा, दो जवान शहीद

एजेंसी। बारामूला

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में मंगलवार को उपकरणों के रख-रखाव के दौरान एक हैंड ग्रेनेड फट गया। इस दर्दनाक हादसे में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने इस घटना की पुष्टि की है। बलिदानी जवानों की पहचान महाराष्ट्र के ऐरोली के रहने वाले चव्हाण विक्रम बालकृष्ण और महाराष्ट्र के सतारा जिले की कराड तहसील के शाहपुर के रहने वाले अर्जुन जाधव राजेंद्र के तौर पर हुई है। सैन्य अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा उरी सेक्टर के कमलकोट स्थित सेना के एक शिविर में हुआ। शिविर में सैन्य उपकरणों और हथियारों के नियमित हस्तांतरण का काम चल रहा था। इसी दौरान एक हैंड ग्रेनेड अचानक डिफ्यूज होने के बजाय फट गया। विस्फोट की चपेट में आने से ड्यूटी पर तैनात दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके के तुरंत बाद शिविर में अफरा-तफरी मच गई। साथी जवानों और अधिकारियों ने बिना वक्त गंवाए दोनों घायल जवानों को तुरंत वहां से निकाला और अस्पताल ले गए। हालांकि, चोटें इतनी गंभीर थीं कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों जवानों को मृत घोषित कर दिया। सैन्य और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में कानून के तहत आवश्यक कानूनी और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आम लोगों को सालाना 8,400 की बचत : केंद्र

एजेंसी। नई दिल्ली

1600 का सिलेंडर 900 में मिल रहा

हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, इसके बाद केंद्र सरकार ने दावा किया है कि उपभोक्ताओं को अब भी भारी राहत दी जा रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की वास्तविक लागत 1,600 से अधिक है, जबकि उपभोक्ताओं को यह मात्र 942 में दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के तर्क के अनुसार, आम उपभोक्ताओं को हर सिलेंडर पर लगभग 700 की अप्रत्यक्ष राहत मिल रही है। इस हिसाब से, अगर कोई परिवार साल में 12 सिलेंडर खर्च करता है, तब उस परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से सालाना 8,400 की बचत हो रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण खनूजा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 की अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलती है। इसके बाद उन्हें प्रति सिलेंडर कुल लगभग 1,000 का लाभ मिल रहा है, जो सालाना 12 सिलेंडरों पर 12,000 तक पहुंच जाता है। हालांकि, इन अप्रत्यक्ष लाभों के बीच, आम आदमी के किचन बजट पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाले बोझ को भी समझना महत्वपूर्ण है। यदि जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक की अवधि के दौरान कोई परिवार हर महीने एक सिलेंडर लेता है, तब मार्च और जून में हुई कीमत वृद्धि के कारण उसकी जेब पर सीधा असर पड़ा है। मार्च से मई तक 120 और जून में 89 का अतिरिक्त खर्च आया। यदि दिसंबर तक कीमतें स्थिर रहती हैं, तब इस साल आम उपभोक्ताओं को अपने किचन बजट पर 803 का सीधा अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए स्थिति और भी जटिल है। एक ओर, उन्हें बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी ओर, सब्सिडी में कटौती की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। पहले उन्हें नौ सिलेंडर पर कुल 2,700 की सब्सिडी मिलती थी, जो अब घटाकर केवल चार सिलेंडर पर 1,200 कर दी गई है। इसका मतलब है कि उन्हें सीधे 1,500 का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार, यदि कोई उज्ज्वला लाभार्थी साल में 12 सिलेंडर का उपयोग करता है, तब बढ़ी हुई कीमतों के 803 के बोझ के साथ-साथ सब्सिडी कटौती के कारण 1,500 का भी नुकसान होगा। कुल मिलाकर, इस श्रेणी के उपभोक्ताओं पर सालाना 2,303 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

ऐतिहासिक गुरुधामों के दर्शन करने सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था पाक रवाना

अमृतसर। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देवजी के शहीदी दिवस पर बुधवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुधामों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयघोष के बीच यह जत्था अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान गया। श्रद्धालु 20 जून तक विभिन्न गुरुधामों के दर्शन कर भारत लौटेंगे। इस जत्थे की अगुवाई एसजीपीसी सदस्य भूपिंदर सिंह भलवान कर रहे हैं, जबकि गुरमीत सिंह बहू को उप-नेता बनाया है। जानकारी के मुताबिक कुल 561 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट वीजा के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 541 को पाकिस्तान उच्चायोग की ओर से वीजा जारी किया गया है, जबकि 20 श्रद्धालुओं के वीजा आवेदन अस्वीकार कर दिए गए। जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि पाकिस्तान स्थित गुरु नानक देवजी के जन्मस्थान ननकाना साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुधामों के दर्शन करना उनके जीवन का सपना था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोगा जिले के एक श्रद्धालु ने कहा कि उन्हें दस दिन का वीजा मिला है और वह पहली बार इन पवित्र स्थलों के दर्शन करने पाकिस्तान जा रहे हैं।

गाजियाबाद के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मिला पोलियोवायरस

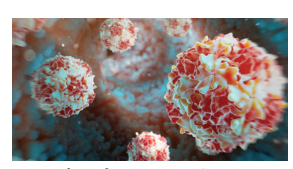

गाजियाबाद। भारत के पोलियो मुक्त अभियान को एक बड़ा झटका लगा है। गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा स्थित एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) से लिए गए दूषित पानी के नमूने की जांच में वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (वीडीपीवी) टाइप-1 की पुष्टि हुई है। इस चौंकाने वाली रिपोर्ट के सामने आते ही स्थानीय स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए शहरी क्षेत्र की 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के तहत 107 टीमों को तैनात किया है, जो घर-घर जाकर बच्चों की सेहत की जांच करेंगी और उन्हें पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगी। दरअसल, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोलियोवायरस की नियमित निगरानी के लिए हर महीने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दूषित पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत हाल ही में डूंडाहेड़ा एसटीपी से भी सैंपल लेकर दिल्ली की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था। सोमवार को विभाग को प्राप्त हुई इस जांच रिपोर्ट ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि इसमें वीडीपीवी टाइप-1 वायरस सक्रिय पाया गया।

नीति आयोग की बैठक गुरुवार को, केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने पर होगी चर्चा

एजेंसी। नई दिल्ली

नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गयी है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाने, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों के बेहतर उपयोग पर चर्चा होगी। नीति आयोग के अनुसार इस वर्ष बैठक का विषय 'विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास' रखा गया है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के समग्र विकास और कल्याण के लिए साझा रणनीति तैयार करना है। बैठक प्रधानमंत्री मोदी के 'टीम इंडिया' के विजन के अनुरूप आयोजित की जा रही है। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, केंद्रीय मंत्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि विकसित भारत के लक्ष्य को ठोस और मापनीय परिणामों में कैसे बदला जाए ताकि देश के हर नागरिक को इसका लाभ मिल सके। बैठक में समावेशी मानव विकास ढांचे के चार प्रमुख स्तंभों पर चर्चा होगी। इनमें आधारभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार एवं उद्यमिता, स्वास्थ्य-पोषण एवं कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा शामिल हैं। इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और देशभर में टिकाऊ रोजगार अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में राज्यों के विकास दृष्टिकोण को राष्ट्रीय समावेशी मानव विकास दृष्टि के साथ जोड़ने पर विशेष बल रहेगा, ताकि संतुलित और टिकाऊ विकास के लिए एकीकृत रणनीति तैयार की जा सके।

कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2ए को दी मंजूरी, एयरपोर्ट तक पहुंचेगी मेट्रो

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-2ए (कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर) को मंजूरी दे दी है। 6.032 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में पांच स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें चार एलिवेटेड और एक भूमिगत स्टेशन शामिल होगा। परियोजना की कुल लागत 2,169.04 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोटेश्वर रोड-एयरपोर्ट कॉरिडोर को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि छह किलोमीटर लंबे इस मार्ग में पांच स्टेशन होंगे और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एयरपोर्ट को सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव से जोड़ेगा, जिसे राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर विकसित किया जा रहा है। परियोजना को चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फेज-2ए के तहत बनने वाले स्टेशनों में आश्रम रोड, कोटेश्वर प्राचीन मंदिर, साबरमती नदी, सरदार नगर और एयरपोर्ट स्टेशन शामिल हैं। इस चरण के पूरा होने के बाद अहमदाबाद-गांधीनगर में सक्रिय मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 77.63 किलोमीटर हो जाएगी। सरकार के अनुसार यह परियोजना एयरपोर्ट, आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा से जोड़ेगी तथा मौजूदा अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क के साथ निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगी। इससे शहरी आवागमन आसान होगा, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2029 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए आसपास स्पोर्ट्स सुविधाएं भी विकसित किए जाने की संभावना है। सरकार के मुताबिक परियोजना से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, निवेश आकर्षित होगा और कम विकसित क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों के लोगों को सार्वजनिक परिवहन की समान सुविधा उपलब्ध होने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

दीघा जगन्नाथ मंदिर से धाम शब्द हटा, समाप्त हुआ वर्षों पुराना विवाद

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के नाम से धाम शब्द हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसले की घोषणा की। उन्होंने यह कदम ओडिशा सरकार की लगातार आपत्ति और अनुरोधों के बाद उठाया गया है, इसके साथ ही उस विवाद का अंत हो गया है, जिस विवाद ने ओडिशा के लोगों और 12वीं सदी के पुरी जगन्नाथ मंदिर के लाखों भक्तों की भावनाओं को आहत किया था। कैबिनेट में हुए फैसले के बारे में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दीघा जगन्नाथ मंदिर के लिए धाम शब्द का इस्तेमाल सनातन संस्कृति के अनुरूप नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली सरकार ने इस श्री श्री जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर के रूप में मंजूरी दी थी, जो तकनीकी रूप से एक सांस्कृतिक केंद्र था, लेकिन इसके नाम में धाम शब्द जोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि यह निर्माण जनता के पैसे से हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए धाम शब्द को तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। हालांकि, इस मंदिर में भगवान की पूजा-अर्चना जगन्नाथ संस्कृति के रीति-रिवाजों के अनुसार पहले की तरह ही होती रहेगी।

संक्षिप्त समाचार

मालवीय नगर अग्निकांड में होटल मालिक और मैनेजर 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड में होटल मालिक लवकेश बजाज और होटल के मैनेजर जय मिश्रा को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो लवकेश बजाज को सभी जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं।बुधवार को दोनों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 8 जून को इस मामले में गिरफ्तार कुक केशव नेगी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। आठ जून को ही जय मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर किया था। कुक केशव नेगी को 6 जून को, जबकि लवकेश बजाज को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था।पुलिस के मुताबिक होटल में आग केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैली। आग लगने के बाद केशव नेगी खुद को बचाने के लिए भाग गया। केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था, तभी उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी, जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद होने से कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए। होटल में 2 कमरे थे। होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था। होटल की खिड़कियों को स्थायी रुप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था। तीन जून को मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में बेसमेंट में फंसे 21 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी और कई लोग झुलस गए थे। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी हैं।

डीपी वर्ल्ड और नीति आयोग ने शीर्ष 10 महिला उद्यमियों को किया सम्मानित

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड और नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) ने बुधवार को 'वी राइज' के समापन पर नई दिल्ली में शीर्ष 10 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। इंडिया हैबिटैट सेंटर के जूनिपर हॉल में शीर्ष 10 महिला उद्यमियों को फूड, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, ब्यूटी एंड वेलनेस समेत विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेटिव एवं प्रभावी कारोबार के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। इन सभी को देशभर से मिले 600 से अधिक आवेदनों में से चुना गया है। ये सभी फाइनलिस्ट भारत के व्यापार एवं आर्थिक विकास की कहानी में हिस्सा लेने की महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की बढ़ती महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करती हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज ने कहा कि एक क्रिकेटर के तौर पर मैं जानती हूं कि हर उपलब्धि सही तैयारी, रेजिलिएंस और सही समय पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देने के साहस का परिणाम होती है। नीति आयोग और डीपी वर्ल्ड के 'वी राइज' प्रोग्राम के माध्यम से सम्मानित महिला उद्यमियों ने भी आगे बढ़ने की वही भावना प्रदर्शित की है, अपनी ताकत को साबित किया है और वैश्विक बाजार के लिए कारोबार खड़ा किया है। उनका सफर हमें याद दिलाता है कि जब अवसर और दृढ़ इच्छाशक्ति को साथ मिलाया जाता है, तो भविष्य का सिर्फ सपना नहीं देखा जाता, बल्कि उसे साकार भी किया जाता है। नीति आयोग की प्रधान आर्थिक सलाहकार एवं महिला उद्यमिता मंच की मिशन डायरेक्टर अन्ना रॉय कहा कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है और ऐसे में उद्यमिता एवं व्यापार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना ज्यादा समावेशी एवं रेजिलिएंट इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 'वी राइज' को एक ऐसे व्यापक प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया है, जो महिला उद्यमियों को कौशल और आत्मविश्वास देता है। साथ ही सतत तरीके से विस्तार करने और वैश्विक बाजार में सार्थक भागीदारी के लिए जरूरी मार्केट ओरिएंटेशन भी प्रदान करता है।' डीपी वर्ल्ड के कंट्री मैनेजर सबकॉन्टिनेंट (इंडिया) हेमंत कुमार रुइया ने कहा कि महिला उद्यमी इनोवेशन, रोजगार सृजन और मजबूत समाज के साथ भारत के आर्थिक भविष्य को आकार दे रही हैं। नीति आयोग के वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर संचालित 'वी राइज' प्रोग्राम के माध्यम से डीपी वर्ल्ड क्षमता बढ़ाने, नेटवर्क का विस्तार करने और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का अवसर देते हुए महिला उद्यमियों की सहायता कर रही है। यह पहल एक समावेशी ट्रेड इकोसिस्टम तैयार करने और उद्यमिता एवं इनोवेशन के माध्यम से भारत के विकास में योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को मिली जमानत

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को जमानत दे दी है। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि खुर्रम परवेज चार साल से ज्यादा समय से हिरासत में है और ट्रायल के जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि खुर्रम परवेज 2004 में लैंडमाइंस में विस्फोट से अपना पैर गंवा चुका है। वो शारीरिक रुप से कमजोर है और उस पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। कोर्ट ने खुर्रम परवेज को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और बिना कोर्ट की अनुमति के दिल्ली के बाहर नहीं जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने खुर्रम परवेज को इस केस के बारे में सार्वजनिक रुप से कोई बयान जारी नहीं करने का आदेश दिया है। खुर्रम परवेज जम्मू एंड कश्मीर कोलीशन ऑफ सिविल सोसायटी का प्रोग्राम कोआर्डिनेटर और एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवालंटरी डिसैपियरेंसेस का चेयरपर्सन है। उसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 22 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। एनआईए के मुताबिक खुर्रम परवेज भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता की आड़ में लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य के साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क संचालित करता था। एनआईए ने इस मामले में नवंबर 2021 में मामला दर्ज किया था। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तोएबा के आतंकियों ने खुर्रम परवेज, मुनीर अहमद कटारिया, अर्शीद अहमद टोंच और जफर अब्बास के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और भारत में आतंकी घटनाओं के लिए एक नेटवर्क चलाने की साजिश रची थी। आरोपितों ने सुरक्षा बलों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, तैनाती और आवाजाही के बारे में जानकारी जुटाकर लश्कर-ए तोएबा तक पहुंचाया था। साथ ही हिमाचल प्रदेश के रहने वाले और सरकारी अधिकारी ने उन्हें आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराए।

अभाविप की डीयू इकाई ने परास्नातक प्रवेशार्थियों की सहायता के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए परास्नातक प्रवेश प्रक्रिया का आरंभ चुका है। देश के अलग-अलग हिस्सों से हजारों विद्यार्थी डीयू का हिस्सा बनने के लिए आवेदन कर चुके हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्रों की सहायता हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) डीयू इकाई ने प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों की सहायता हेतु अपना विस्तृत 'अभाविप हेल्पलाइन नंबर' जारी किया है। अभाविप ने बताया कि दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कई छात्रों को तकनीकी जानकारी के अभाव में प्रवेश प्रक्रिया, फॉर्म भरने, कट-ऑफ और पाठ्यक्रम चयन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के त्वरित समाधान के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अभाविप ने विषय अनुसार कार्यकर्ताओं की एक हेल्पलाइन टीम गठित की है। अभाविप डीयू इकाई अध्यक्ष अभिनव चौधरी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना लेकर देश के हर कोने से छात्र आते हैं। कई बार सही जानकारी के अभाव में उन्हें फॉर्म भरने या काउंसलिंग के दौरान बेवजह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अभाविप का 'सहायता संपर्क सूत्र' यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी मेधावी छात्र का सपना केवल जानकारी की कमी से न टूटे। अभाविप डीयू इकाई मंत्री अक्षय प्रताप ने कहा कि विद्यार्थी परिषद केवल एक संगठन नहीं, बल्कि डीयू में कदम रखने वाले हर नए छात्र का परिवार है। कल पहले चरण का पंजीकरण होने के तुरंत बाद से ही अभाविप इकाई पूरी तरह सक्रिय हो गई है। अभाविप हमेशा की तरह छात्र हितों के लिए ढाल बनकर खड़ी है। ये सभी हेल्पलाइन नंबर हमने पंजीकरण के पहले चरण की शुरुआत के साथ ही जारी किया था जिसके माध्यम से हमारे कार्यकर्ता सैकड़ो छात्रों की सहायता कर चुके है।

स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सदतपुर वार्ड का किया निरीक्षण

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बुधवार को शाहदरा (उत्तरी) जोन के सदतपुर वार्ड का निरीक्षण किया। शर्मा ने वार्ड में सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित रूप से सफाई कार्यों की निगरानी सुनिश्चित की जाए, जिससे क्षेत्र में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बना रहे। शर्मा ने र्डि में हो रहे अवैध अतिक्रमणों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित निगरानी रखी जाए तथा आवश्यकता अनुसार नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी अपनी समस्याएं बताईं। इस पर स्थायी समिति अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान किया जाए। तुकमीरपुर रोड के निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर खुली नालियां पाई गईं। इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी खुली नालियों को शीघ्र ढका जाए, ताकि उनमें कूड़ा-कचरा न डाला जा सके और जल निकासी बाधित न हो। आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी नालियों की समयबद्ध डी-सिल्टिंग कराने पर विशेष बल दिया और निर्देश दिए कि एमसीडी के अधिकार क्षेत्र की सभी नालियों की सफाई प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरी की जाए, ताकि जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। निरीक्षण के दौरान तुकमीरपुर रोड पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आने वाले एक बड़े नाले का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि नाले के कई हिस्सों में बाउंड्री वॉल का अभाव है तथा सफाई की आवश्यकता है। इस संबंध में सत्या शर्मा ने आश्वासन दिया कि इस विषय को संबंधित विभाग के समक्ष उठाया जाएगा और आवश्यक समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं संबंधित विभाग को पत्र लिखकर आगामी मानसून से पूर्व नाले की सफाई और सुरक्षा संबंधी कार्य पूर्ण कराने का प्रयास करेंगी। स्थायी समिति अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि वार्ड में स्वच्छता बनी रहे और मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इस दौरान उनके साथ स्थानीय पार्षद नीता बिष्ट, उपायुक्त ममता यादव तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट ने अमरावती में दो बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को दी मंजूरी

लोकतंत्र की शान

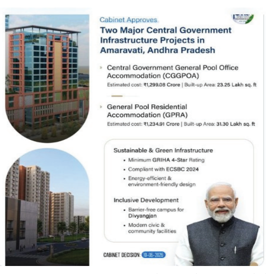

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में दो प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए जनरल पूल ऑफिस आवास (सीजीजीपीओए) और कर्मचारियों के लिए जनरल पूल रेजिडेंशियल आवास (जीपीआरए) शामिल हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां राष्ट्रीय मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना का विकास करना है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने अमरावती में केंद्रीय सरकारी जनरल पूल ऑफिस आवास परियोजना को 1,299.08 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है। इस परियोजना में 23.25 लाख वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र होगा। साथ ही जनरल पूल रेजिडेंशियल आवास परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 1,234.91 करोड़ रुपये है और इसमें 31.30 लाख वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र होगा।उन्होंने बताया कि दोनों परियोजनाएं सस्टेनेबल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों पर आधारित होंगी। इनमें न्यूनतम एकीकृत आवास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग (गृहा) 4-स्टार रेटिंग सुनिश्चित की जाएगी और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी 2024) के अनुरूप डिजाइन तैयार किया जाएगा। भवनों को ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में समावेशी विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। परिसर को दिव्यांगजन के लिए बाधा-मुक्त बनाया जाएगा और आधुनिक नागरिक एवं सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अभिषेक मनु सिंघवी ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने को बताया गैर-कानूनी, चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने का मामला राजनीतिक और कानूनी विवाद का विषय बन गया है। कांग्रेस ने इस फैसले को पूरी तरह अवैध और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत बताते हुए चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस के विधि, सूचना का अधिकार (आरटीआई) एवं मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कानून की नजर में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उनके नामांकन को रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं बनता। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे कानून की गलत व्याख्या बताया। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं संचार, प्रचार और मीडिया विभाग की प्रमुख रुचिरा चतुर्वेदी द्वारा सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में सिंघवी ने कहा कि वह वर्तमान में विदेश में हैं, लेकिन उन्होंने मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से इस मामले में विस्तार से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि यह जानकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नटराजन का नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया, जबकि उनके खिलाफ कोई ऐसा आपराधिक मामला दर्ज नहीं है जिसका उल्लेख नामांकन पत्र में करना अनिवार्य हो।सिंघवी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर निजी शिकायत तब तक आपराधिक मामला नहीं मानी जाती, जब तक संबंधित मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस पर संज्ञान नहीं लेता। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में केवल एक नोटिस जारी हुआ था, जबकि अदालत ने अभी तक मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे में इसे आपराधिक मामला मानना न्यायिक सिद्धांतों और स्थापित कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायशास्त्र और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों में यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्थापित है कि केवल नोटिस जारी होना किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कांग्रेस ने यह कानूनी पक्ष रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष भी रखा था, लेकिन इसके बावजूद नामांकन रद्द कर दिया गया। सिंघवी ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि यदि तथ्यों और कानून के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लिया जाता, तो नामांकन पत्र अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि वह अपने प्रशासनिक और संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए इस फैसले की समीक्षा करे और इसे निरस्त करे। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति को स्वीकार करते हुए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था। भाजपा का आरोप है कि नटराजन ने तेलंगाना में लंबित एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी थी, जो निर्वाचन नियमों के तहत आवश्यक थी।वहीं कांग्रेस का कहना है कि संबंधित मामले में न तो कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज हुई थी और न ही अदालत ने उस पर संज्ञान लिया था। केवल एक नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब नटराजन की ओर से विधिवत दे दिया गया था। इसलिए उसका उल्लेख नामांकन पत्र में करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं था। नामांकन रद्द होने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा और कांग्रेस को पहले से आशंका थी कि चुनावी प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भाजपा को कांग्रेस विधायकों की एकजुटता का एहसास हुआ, तब कानूनी नोटिस को आधार बनाकर उनके नामांकन को चुनौती दी गई। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह केवल 10 करोड़ रुपये के कथित मुआवजे से जुड़ा एक सिविल प्रकृति का नोटिस था, जिसका जवाब पहले ही दिया जा चुका था। उन्होंने नामांकन रद्द करने के फैसले को कानूनी रूप से कमजोर बताया।कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मामले को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को मिलने तक की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राजनीतिक दृष्टि से इस फैसले का असर राज्यसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। यदि कांग्रेस को चुनाव आयोग अथवा उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिलती है, तो मध्य प्रदेश की तीनों रिक्त राज्यसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना बढ़ जाएगी। भाजपा के उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल की जीत पहले से लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है, जबकि तीसरे उम्मीदवार महेश केवट की उम्मीदवारी ने चुनावी मुकाबले को नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। गौरतलब है कि संभावित क्रॉस-वोटिंग या राजनीतिक टूट-फूट की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को पहले ही बेंगलुरु भेज दिया था। अब पार्टी कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में जुटी हुई है।

कंगना रनौत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जताया आभार, 'भारत भाग्य विधाता' को किया टैक्स फ्री घोषित

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। स्टारर फिल्म भारत भाग्य विधाता 12 जून को रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म की रिलीज़ से पहले कंगना अपनी टीम के साथ देशभर में यात्रा कर रही हैं, जहां वे उन असली नायकों को सम्मानित कर रही हैं जो संकट के समय चुपचाप देश की सेवा करते हैं। भुवनेश्वर और रायपुर के बाद यह अभियान दिल्ली पहुंचा, जहां फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस मौके पर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री भी मौजूद रहीं। कंगना और मुख्यमंत्री ने मिलकर दिल्ली के कई रियल-लाइफ हीरोज को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत भाग्य विधाता को दिल्ली में टैक्स फ्री घोषित करने का ऐलान किया। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए, जिनमें अन्नपूर्णा देवी, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉ. राज भूषण चौधरी, प्रताप राव जाधव, गिरिराज सिंह और आशीष सूद प्रमुख रहे। इस अवसर पर कंगना रनौत ने कहा, "मैं हमारी फिल्म की पूरी टीम की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दिल से धन्यवाद करती हूं। उन्होंने दिल्ली के विकास और प्रशासन में जो परिवर्तन किए हैं, वह सराहनीय हैं। जब मैंने उन्हें इस स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी, जिसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी।" वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कंगना की सराहना करते हुए कहा, "कंगना रनौत संसद में एक मजबूत आवाज हैं, जो सिनेमा और देश के लोगों के लिए लगातार संघर्ष करती हैं। उनकी फिल्म यह संदेश देती है कि देशभक्ति केवल वर्दीधारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक के भीतर होती है।" इस विशेष पहल के तहत फिल्म की टीम देशभर में अलग-अलग शहरों में स्क्रीनिंग आयोजित कर रही है, जहां पुलिसकर्मी, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को आमंत्रित कर सम्मानित किया जा रहा है। दिल्ली में भी कई अनदेखे नायकों—निशी पाठक, पुष्पा, सुमन, मेनका, नम्रता यादव, नीति शर्मा, बीके खुराना और शशि लाल—को 'भारत भाग्य विधाता' बैज देकर सम्मानित किया गया। फिल्म को डॉ. जयंतीलाल गड़ा (पेन स्टूडियोज) द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसे पेन स्टूडियोज, मणिकर्णिका फिल्म्स और परमहंस क्रिएशंस ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना पर हैदराबाद में गुरुवार को होगा रोड शो

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय 11 जून को हैदराबाद में अपना अगला रोड शो का आयोजन करेगा। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स पर सफल रोड शो से मिली मजबूत गति को आगे बढ़ाते हुए यह रोड शो किया जायेगा। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी हैदराबाद रोडशो में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे विशिष्ट अतिथि होंगे। कोयला मंत्रालय के मुताबिक यह रोडशो नीतिगत समर्थन, तकनीकी नवाचारों, निवेश के अवसरों और परियोजना कार्यान्वयन रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। ये नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और निवेशकों को एक साथ एक मंच लाएगा ताकि, देशभर में कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए सहयोगात्मक मार्ग ढूंढे जा सकें। इस आयोजन से हितधारकों की सहभागिता को और मजबूत करने, रणनीतिक साझेदारियों को सुगम बनाने और भारत में कोयला गैसीकरण के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम के निर्माण में सहयोग मिलने की आशा है। इन पहलों के माध्यम से कोयला मंत्रालय नवाचार को बढ़ावा देने, उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, संसाधनों के सतत उपयोग और औद्योगिक विकास के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के सरकारी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।मंत्रालय के मुताबिक इस कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त, अपर सचिव सनोज कुमार झा, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, कोयला एवं लिग्नाइट कंपनियों के प्रतिनिधि, प्रौद्योगिकी प्रदाता, उद्योग संघ, निवेशक और अन्य प्रमुख हितधारक भी उपस्थित रहेंगे।

सूरत में सेप्टिक टैंक साफ करते समय 4 मजदूरों की मौत का एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। गुजरात के सूरत जिले में एक आभूषण निर्माण इकाई में सेप्टिक टैंक साफ करते समय चार मजदूरों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस घटना को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए गुजरात के मुख्य सचिव और सूरत पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बुधवार को कहा कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि घटना 7 जून को हुई जब मजदूर बिना किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किए टैंक में सफाई के लिए उतरे और जहरीली गैस के शिकार हो गए। उन्हें बचाव दल द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आयोग ने कहा कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सही है तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। आयोग ने निर्देश दिया है कि रिपोर्ट में जांच की स्थिति और मृत मजदूरों के परिजनों को दी गई क्षतिपूर्ति का विवरण भी शामिल किया जाए। आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि आभूषण की सफाई प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट को उक्त सेप्टिक टैंक में जमा किया जाता था।

प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया रिकॉर्ड, 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा नेताओं ने दिल्ली के धार्मिक स्थलों पर की विशेष पूजा-अर्चना

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दीर्घायु, स्वस्थ एवं सफल नेतृत्व की कामना की। दिल्ली के अनेक प्राचीन मंदिरों में भाजपा नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल सहित कई वरिष्ठ नेता अलग-अलग मंदिरों में पूजा-अर्चना की।भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सांसद बांसुरी स्वराज के साथ झंडेवालान देवी मंदिर में दर्शन कर की। वहीं, मंदिर मार्ग स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में स्वाति मालीवाल और भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पूजा-अर्चना की।12 साल पूरे होने पर नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, जम्मू-कश्मीर में विकास, विश्वस्तरीय हाईवे नेटवर्क, डिजिटल इंडिया और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम को भारत मंडपम में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को पीछे छोड़ते हुए कुल 4399 दिनों तक प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश कि कमान संभाली।

प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घ नेतृत्व काल के लिए प्रार्थना

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली का शानदार प्रदर्शन, विकास एवं राजस्व कार्यों की ओवरऑल रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान

मई 2026 की रैंकिंग में विकास कार्यक्रमों में तृतीय, राजस्व कार्यक्रमों में तृतीय तथा संयुक्त मूल्यांकन में बरेली बना प्रदेश का नंबर-1 जनपद

लोकतंत्र की शान , (बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा), मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत प्रदेश में विकास कार्यों के मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों की सेवाओं, योजनाओं एवं परियोजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक माह जनपदों की रैंकिंग जारी की जाती है। इसी क्रम में माह मई 2026 की जारी रैंकिंग में जनपद बरेली ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश स्तर पर अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय दिया है। जारी रैंकिंग के अनुसार जनपद बरेली

को विकास कार्यक्रमों में प्रदेश में तृतीय स्थान, राजस्व कार्यक्रमों में तृतीय स्थान तथा विकास एवं राजस्व कार्यों की संयुक्त (ओवरऑल) रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि प्रशासनिक दक्षता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकारियों-कर्मचारियों की समन्वित कार्यप्रणाली का परिणाम मानी जा रही है। जनपद प्रशासन के अनुसार यह सफलता किसी एक विभाग की नहीं बल्कि सभी विभागों के संयुक्त प्रयास, सतत अनुश्रवण, समयबद्ध समीक्षा एवं शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य निष्पादन का परिणाम है। विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने, राजस्व संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने तथा जनहित से जुड़े कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन ने बरेली को प्रदेश में अग्रणी स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर जनपद प्रशासन ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा एवं टीम भावना की सराहना करते हुए उन्हें इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रशासन ने यह भी अपेक्षा व्यक्त की है कि आने वाले समय में सभी विभाग इसी उत्साह, प्रतिबद्धता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हुए विकास एवं राजस्व कार्यक्रमों की गति को और अधिक तेज करेंगे।

पीएम मोदी के कीर्तिमान पर चंद्रपाल खड़कवंशी के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम, विशाल भंडारे का आयोजन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा,

हसनपुर/सकरौली: बुधवार को ग्राम सकरौली, विधानसभा हसनपुर-42 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 3499 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोधी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य चंद्रपाल खड़कवंशी के नेतृत्व में बाबा महादेव मंदिर परिसर में विशाल

भंडारे का भी आयोजन हुआ। चंद्रपाल खड़कवंशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उनके नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास के नए आयाम छुए हैं। अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण करोड़ों सनातनियों का सपना साकार हुआ है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर एक भारत-श्रेष्ठ भारत का संकल्प पूरा किया गया। खड़कवंशी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, जनधन जैसी योजनाओं ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है। आज भारत विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। जी-20 की सफल अध्यक्षता ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाई है। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। उपस्थित नागरिकों ने बाबा महादेव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं राष्ट्र निर्माण के संकल्प की निरंतर सफलता के लिए प्रार्थना की। चंद्रपाल खड़कवंशी ने कहा कि मोदी जी का हर निर्णय राष्ट्रहित में होता है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य उनके नेतृत्व में ही पूरा होगा। इस दौरान भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा एवं व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, विक्रांत शर्मा, अर्पण गुप्ता, हुकुम सिंह खड्गवंशी, पवन नेताजी, कलुआ खड़कवंशी आदि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति व युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

रामपुर में श्री खाटू श्याम बाबा के विशाल जागरण में उमड़ा आस्था का सैलाब

लोक तंत्र की शान ,मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर।

श्री श्याम भक्त परिवार द्वारा आयोजित 26वें श्री खाटू श्याम बाबा विशाल जागरण ने सिविल लाइन स्थित आदर्श रामलीला ग्राउंड को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में सजे भव्य श्याम दरबार ने श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया और

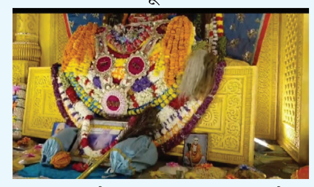

पूरे आयोजन का केंद्र बिंदु बना रहा। जागरण में बाबा श्याम का मनमोहक दरबार रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और धार्मिक झांकियों से सुसज्जित किया गया था। देर रात तक चले भजन-कीर्तन में प्रसिद्ध भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक श्याम भजन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु झूम उठे। "हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा" के जयघोष से पूरा पंडाल गूंजता रहा। कार्यक्रम में रामपुर सहित आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह 26वां विशाल जागरण है, जिसे हर वर्ष श्रद्धा और भव्यता के साथ आयोजित किया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि खाटू श्याम बाबा को कलयुग में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला देव माना जाता है और देशभर में उनके प्रति गहरी आस्था देखने को मिलती है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री श्याम भक्त परिवार के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देर रात तक चले भजनों और बाबा के दरबार के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया।

रामपुर में श्री खाटू श्याम बाबा के विशाल जागरण में उमड़ा आस्था का सैलाब

लोक तंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर।

श्री श्याम भक्त परिवार द्वारा आयोजित 26वें श्री खाटू श्याम बाबा विशाल जागरण ने सिविल लाइन स्थित आदर्श रामलीला ग्राउंड को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में सजे भव्य श्याम दरबार ने श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया और पूरे आयोजन का केंद्र बिंदु बना रहा। जागरण में बाबा श्याम का मनमोहक दरबार रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और धार्मिक झांकियों से सुसज्जित किया गया था। देर रात तक चले भजन-कीर्तन में प्रसिद्ध भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक श्याम भजन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु झूम उठे। "हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा" के जयघोष से पूरा पंडाल गूंजता रहा। कार्यक्रम में रामपुर सहित आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह 26वां विशाल जागरण है, जिसे हर वर्ष श्रद्धा और भव्यता के साथ आयोजित किया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि खाटू श्याम बाबा को कलयुग में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला देव माना जाता है और देशभर में उनके प्रति गहरी आस्था देखने को मिलती है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री श्याम भक्त परिवार के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देर रात तक चले भजनों और बाबा के दरबार के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया।

40 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत, चार बच्चे हुए बेसहारा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर/उझारीः अमरोहा जनपद के सैदनगली थाना क्षेत्र के कस्बा उझारी में बुधवार को 40 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका मूल रूप से संभल जनपद की रहने वाली थी। वह पिछले करीब पांच माह से उझारी कस्बे में किराए के मकान में अपने चार बच्चों के साथ रह रही थी। करीब पांच वर्ष पहले लंबी बीमारी के चलते उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तब से वह मजदूरी कर बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी। बुधवार सुबह महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में पड़ा मिला। महिला के बच्चों ने बताया कि महिला की दूसरी शादी होने वाली थी और जिससे शादी होने वाली थी वह रात आया हुआ था और हम चारों भाई बहन ऊपर सोए थे तथा मम्मी और वह आदमी जिससे शादी होने वाली थी नीचे चटाई पर सोए थे सुबह वह आदमी तो नहीं मिला लेकिन मम्मी की लाश खून से लतपथ हमें दिखाई दी, हमने शोर मचा के पड़ोसियों को इकट्ठा किया वही पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास के लोगों और मकान मालिक से पूछताछ कर रही है। सीओ हसनपुर पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने कहा कि सभी पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है। मौत हत्या है या आत्महत्या, इसका खुलासा जांच के बाद होगा। टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इधर मां की मौत के बाद चारों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। पड़ोसी बच्चों को संभाल रहे हैं। घटना के बाद कस्बे में शोक की लहर है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

भीषण गर्मी में राहतः साहनपुर को मिला नया ट्यूबवेल पेयजल संकट से मिलेगी निजात खुर्शीद मंसूरी

लोक तंत्र की शान, खिज़र अहमद

साहनपुर/बिजनौर। भीषण गर्मी के बीच साहनपुर नगर पंचायत ने क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत देते हुए मोहल्ला सानीयान में नए ट्यूबवेल का सफलतापूर्वक संचालन शुरू कर दिया है। ट्यूबवेल के चालू होने से मोहल्ला सानीयान

सहित आसपास के कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा और लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। नगर पंचायत द्वारा किए गए इस कार्य को स्थानीय लोग गर्मी के मौसम में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। बढ़ते तापमान और जल संकट के बीच नए ट्यूबवेल से हजारों लोगों को नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। नगर पंचायत प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के तहत विभिन्न विकास कार्यों को लगातार गति दी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में भी जलापूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय नागरिकों ने नए ट्यूबवेल के संचालन पर खुशी जताते हुए नगर पंचायत का आभार व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि गर्मी के दिनों में पानी की समस्या सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है, ऐसे में यह पहल आमजन के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

गंगवार, बुरावली सहित अनेकों ग्रामों में भूमि की मूल्य दरों में वृद्धि नहीं यह जाने की शिकायत जयंत चौधरी से की

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल रूहेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय महासचिव मुजाहिद चौधरी एडवोकेट तथा युवा रालोद अमरोहा2 के जिला अध्यक्ष इरकान अली ने रालोद अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री कौशल विकास (भारत सरकार) से नई दिल्ली में भेंट की ओर ज्ञापन सौंपा । रालोद नेता मुजाहिद चौधरी ने हसनपुर लौट कर यह जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने जयंत चौधरी को बताया कि जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर के ग्रामों की सर्किल भूमि मूल्यांकन दर सूची 2025-26 में संशोधित की गई थी । जिसमें ग्राम हसनपुर गंगवार, बुरावली सहित अनेकों ग्रामों में भूमि की मूल्य दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई । इससे पूर्व भी जनपद में मूल्य दर सूची संशोधित करते समय तहसील हसनपुर के ग्रामों को भूमि मूल्य वृद्धि से मुक्त रखा गया था । अब पुनः जनपद अमरोहा में भूमि मूल्यांकन सर्किल दर सूची का नवीनीकरण/ संशोधन की कार्यवाही चल रही है। श्री चौधरी ने बताया कि ग्राम गंगवार, हाकमपुर, बुरावली तहसील हसनपुर के अति विकसित ग्रामों की श्रेणी में आते हैं । जिस कारण यहां जमीनों की वास्तविक कीमत काफी ज्यादा है । इन विकसित ग्रामों को जनपद में हुई दो बार मूल्य सूची में वृद्धि में शामिल नहीं किया जाना इन ग्रामों के किसानों के साथ घोर अन्याय है। वर्तमान में प्रचलित मूल्य दर सूची तथा भूमि की वास्तविक व बाजारी कीमत में बहुत अंतर है । श्री चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों तथा अधिवक्ताओं द्वारा 2025- 26 में प्रस्तावित भूमि मूल्यांकन सूची के विरुद्ध आपत्ति करते हुए इन ग्रामों की भूमि की दरों को बढ़ाने की मांग की गई थी । परंतु इन ग्रामों की भूमि की दरें नहीं बढ़ाई गईं । श्री चौधरी ने जनहित में जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर के ग्राम हाकमपुर, गंगवार, बुरावली तहसील हसनपुर की कृषि, आवासीय, अनआवासीय भूमि की दरें हसनपुर -रहरा -गंवा प्रांतीय राजमार्ग पर स्थित अन्य ग्रामों के समान बढ़ाये जाने की मांग की । श्री चौधरी ने इस अवसर पर जयंत चौधरी को अपना काव्य संग्रह # मजबूर सांसें फिसलती जिंदगी... की प्रति भी भेंट की।

बरेली में ED का बड़ा एक्शनः मोबाइल कारोबारी आशुतोष अग्रवाल के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी, 100 करोड़ GST चोरी का आरोप

» **दिुस्तान लीवर, ITC और कैडबरी के डिस्ट्रीब्यूटर पर जांच तेज, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क की पड़ताल**

लोक तंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) बरेली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बड़ी कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। शहर के चर्चित मोबाइल कारोबारी आशुतोष अग्रवाल के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर जांच एजेंसी की टीम ने डेरा डाले रखा। यह पूरा मामला 100 करोड़ रुपये से अधिक की कथित GST चोरी, संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच की दिशा उस समय और तेज हुई जब पंजाब से जुड़े आर्थिक अपराध मामलों में कुछ नए वित्तीय लिंक सामने आने की बात सामने आई।

सुबह 7 बजे शुरू हुई कार्रवाई, देर रात तक चली जांच–सूत्रों के अनुसार ED की टीम ने बुधवार सुबह सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित कारोबारी प्रतिष्ठान और संबंधित परिसरों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। मारवाड़ीगंज स्थित आवासीय परिसर, कार्यालय और गोदाम को जांच के दायरे में लिया गया। टीम ने मौके से कंप्यूटर सिस्टम, हार्ड डिस्क, मोबाइल डिवाइस, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण फाइलों को कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू की। अधिकारियों का मुख्य फोकस यह समझना रहा कि व्यापारिक लेनदेन की वास्तविक प्रकृति क्या थी तथा कहीं फर्जी कंपनियों के माध्यम से कर लाभ और धन हस्तांतरण की व्यवस्था तो नहीं बनाई गई।

GST इनपुट टैक्स क्रेडिट और फर्जी कंपनियों का नेटवर्क जांच के केंद्र में–जांच एजेंसियों को आशंका है कि कुछ कंपनियों के जरिए कथित तौर पर फर्जी खरीद-बिक्री दर्शाकर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ लिया गया। प्रारंभिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या कई कागजी कंपनियों के माध्यम से कारोबार का आकार वास्तविक से अलग प्रस्तुत किया गया।

मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी पर पुलिस का कड़ा एक्शन, 5 घंटे में चला बुलडोजर

लोक तंत्र की शान , मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

मंडल मुरादाबाद। जिलाअमरोहा (रहता): 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद फरार आरोपी के अवैध निर्माण को पुलिस ने जेसीबी से किया ध्वस्त, आरोपी की तलाश में 4 टीमें तैनात।अमरोहा।थाना रहरा क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आरोपी पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। आत्मसमर्पण का अल्टीमेटम खत्म होने के महज 5 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी के घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना रहरा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 8 वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला आरोपी फरमान अली वहां पहुंचा। वह बच्ची को बहला-फुसलाकर अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर खेतों की तरफ ले गया, जहां उसने मासूम के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया।वारदात के बाद लहूलुहान और रोती-बिलखती मासूम किसी तरह अपने घर पहुंची। बच्ची के कपड़ों पर खून के निशान देख परिजनों के होश उड़ गए। जब परिजनों ने उससे पूछताछ की, तो मासूम ने आपबीती सुनाई। बदहवास परिजन तुरंत बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की तहरीर दी घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) लखन सिंह यादव तुरंत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम जब आरोपी फरमान अली को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची, तो वह फरार मिला। पुलिस ने आरोपी के परिजनों को सख्त चेतावनी देते हुए 5 घंटे के भीतर उसे आत्मसमर्पण कराने का अल्टीमेटम दिया था। ऐसे घिनौने अपराधियों के खिलाफ हमेशा कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा।अल्टीमेटम की अवधि बीत जाने के बाद भी जब आरोपी हाजिर नहीं हुआ, तो पुलिस-प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। राजस्व टीम से आरोपी के मकान की पैमाइश कराई गई, जिसमें उसका एक कमरा और बाथरूम अवैध पाया गया। रात करीब 8 बजे पुलिस ने मौके पर जेसीबी (बुलडोजर) बुलाई और आरोपी के अवैध कमरे व बाथरूम को ढहा दिया। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बैलगाड़ी के ठेले को भी तोड़ दिया गया।प्रशासन के इस त्वरित और कड़े एक्शन को देखने के लिए मौके पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स लगातार गश्त कर रही है। वहीं, इस त्वरित कार्रवाई पर पीड़ित परिवार ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा,हमें पुलिस से ऐसी ही कठोर कार्रवाई की उम्मीद थी।

विधायक हाजी तसलीम अहमद ने वन गुर्जर परिवारों को दी सोलर लाइट की सौगात

विधायक तसलीम अहमद के सौजन्य से जगमगा रही नजीबाबाद विधान सभा

लोक तंत्र की शान/ खिजर अहमद

नजीबाबाद। क्षेत्र के ग्राम जाफराबाद में विधायक नजीबाबाद हाजी तसलीम अहमद ने अपनी विधायक निधि से 13 वन गुर्जर परिवारों को सोलर लाइट उपलब्ध कराकर बड़ी राहत दी। विधायक ने स्वयं

मौके पर पहुंचकर लाभार्थी परिवारों के घरों में सोलर लाइट लगवाने का कार्य अपने सामने संपन्न कराया। ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सोलर लाइट मिलने से उन्हें रात के समय बेहतर रोशनी की सुविधा मिलेगी तथा दैनिक जीवन में काफी सहूलियत होगी। इस अवसर पर खुर्शीद प्रधान, ज़ाहिद अंसारी, अनवर खान मंसूब, नितिन कश्यप, शमशेर आलम, मूसा, समी, गुलाम मोहम्मद सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक हाजी तसलीम अहमद ने कहा कि क्षेत्र के विकास और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वह लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा।

उत्तराखंड सीमा से यूपी में ओवरलोड डंपरों का खेल

» **ओवर लोड डंपरों ने कई को मौत की नींद सुला दिया प्रशाशन बे खबर**

» **आखिर क्यों खामोश हैं जिम्मेदार विभाग?**

लोक तंत्र की शान, खिजर अहमद

नजीबाबाद/बिजनौर। उत्तराखंड सीमा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले रेत-बजरी से लदे ओवरलोड और ओवरहाइट डंपरों का संचालन इन दिनों जनपद बिजनौर में गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। हरिद्वार-नजीबाबाद मार्ग से होकर थाना मंडावली क्षेत्र में दिन-रात दौड़ रहे भारी वाहनों को लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि सड़क सुरक्षा, सरकारी संपत्तियों और आम नागरिकों की जान से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संबंधित विभागों की कार्रवाई धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। ग्राम भागूवाला स्थित स्वामी अवधेशानंद पुलिस चौकी और वन विभाग चौकी के सामने से प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारी वाहन गुजर रहे हैं। इसके बावजूद ओवरलोड एवं ओवरहाइट वाहनों का संचालन लगातार जारी रहने से निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भागूवाला क्षेत्र में नहरवाई के सामने पुलिया निर्माण कार्य चल रहा है और सड़क का एक हिस्सा ही यातायात के लिए उपयोग में है। ऐसे में भारी वाहनों का दबाव और तेज रफ्तार किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति गंभीर हो सकती है।

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भंडारे का आयोजन विधायक महेंद्र खड़कवंशी ने गिनाईं उपलब्धियां

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बुधवार को हसनपुर विधानसभा के ग्राम बिजनौरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विश्वास, विकास और जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिव मंदिर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हसनपुर विधायक महेंद्र खड़कवंशी मुख्य अतिथि रहे। विधायक खड़कवंशी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश-प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, युवा और महिला उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। विधायक ने कहा कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और जी-20 की सफल अध्यक्षता से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रदेश में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर निवेश का माहौल बनाया है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। विधायक ने सभी से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब हर नागरिक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाएगा। इस अवसर पर हसनपुर ब्लॉक प्रमुख ममता गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष मयंक अग्रवाल, अभिनव कौशिक, हिमांशु त्यागी, ऊझारी मंडल अध्यक्ष कल्याण सिंह सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान संघ श्रीकृष्ण शर्मा, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हेमराज सैनी, भाजपा नेता अंकुर अग्रवाल, मुदित गुर्जर, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शिखर अग्रवाल, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र खड़कवंशी, प्रधान संघ अध्यक्ष यशपाल प्रधान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। भंडारे में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया।

संक्षिप्त समाचार

एनएच-107 पर निर्माण कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता व समय-सीमा पर दिया जोर

लोकतंत्र की शान : सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः आज दिनांक 10 जून 2026 को जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार ने सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-107 पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) एवं ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा रानीहाट से बबुजन घाट तक बन रही सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दोनों परियोजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप कार्य निष्पादन की स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए तथा शेष कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि इन महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और स्थानीय विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित निगरानी बनाए रखी जाए। इस दौरान उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर श्री आलोक राय, संबंधित तकनीकी पदाधिकारी एवं कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ट्रेन के गेट पर लटककर बनाई वीडियो, 2000 जुर्माना

लोकतंत्र की शान , हाजीपुर। वैशाली में चलती ट्रेन के गेट पर लटककर वीडियो बनाने वाली एक महिला पर राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) ने कार्रवाई की है। GRP ने महिला को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद न्यायालय ने उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। महिला को भविष्य में ऐसी कोई भी गैर-जिम्मेदाराना हरकत न करने की चेतावनी भी दी गई है। यह मामला तब सामने आया जब हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में एक महिला चलती ट्रेन के गेट को पकड़कर बाहर लटकी हुई थी और वीडियो बना रही थी। वीडियो में महिला को यह कहते हुए सुना गया था, "हम वीडियो बनवईबई त कोई बोलतई रें।" वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी ने मामले को गंभीरता से लिया। जीआरपी ने महिला को नोटिस जारी कर रेलवे सुरक्षा पोस्ट हाजीपुर में पूछताछ के लिए बुलाया। जीआरपी थाना की एसआई शालिनी गुप्ता ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। पूछताछ के दौरान महिला ने अपनी पहचान पिंकी देवी, पति अनिल पासवान, निवासी दुबहा वार्ड नंबर 3, थाना सहदेई बुजुर्ग के रूप में बताई। उसने स्वीकार किया कि उसने जून महीने में हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाते समय ट्रेन में यह वीडियो बनाया था। जांच और पूछताछ के बाद महिला पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पिंकी देवी ने भविष्य में ऐसी कोई गलती न दोहराने और इस तरह का कोई वीडियो न बनाने का आश्वासन दिया है।

वैशाली में बिजली कर्मी पर ईंट से हमला, खराब ट्रांसफार्मर ठीक करते समय पिटाई, वीडियो वायरल

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली के महुआ प्रखंड स्थित मुकुंदपुर वार्ड संख्या 23 में एक बिजली कर्मी पर हमला किया गया है। यह घटना 9 जून की दोपहर को हुई, जब कर्मी श्रवण गिरी कब्रिस्तान के पास खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहे थे। श्रवण गिरी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई की। पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर ईंट और बांस का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। घायल कर्मी को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला करने वाले युवकों की पहचान मोहम्मद सेराज, मोहम्मद इस्तियाक और मोहम्मद शफी के रूप में हुई है, जो सभी मुकुंदपुर गांव के निवासी हैं। घायल कर्मी श्रवण गिरी (पिता रामेश्वर गिरी) ने विद्युत विभाग के कनीय अभियंता सुशांत कुमार को लिखित आवेदन दिया है। उन्होंने अपने आवेदन में तीन आरोपियों को नामजद किया है। पीड़ित ने बताया कि हमलावरों ने उनके सिर पर ईंट से और सीने व हाथ पर बांस से वार किया। घटना के समय मौके पर मौजूद अन्य बिजली कर्मियों ने श्रवण गिरी को तुरंत अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित बिजली कर्मी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कनीय अभियंता सुशांत कुमार ने बताया कि आवेदन मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महुआ थाना अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने पुष्टि की कि उन्हें मामले का आवेदन प्राप्त हुआ है और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद बिजली कर्मियों में चिंता का माहौल है। उन्होंने फील्ड में काम के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

आईसीयू ड्यूटी छोड़ भागने के आरोप में डॉक्टर निलंबित

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर प्रसाद अस्पताल आईसीयू अग्निकांड मामले में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। सात मरीजों की जान लेने वाली इस घटना के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईसीयू ड्यूटी के दौरान मरीजों को छोड़कर चले जाने के आरोपी डॉक्टर पंकज कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जिले में चल रहे विशेष जांच अभियान के तहत अब तक 25 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों को सील किया जा चुका है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बंदरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि 4 जून को प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में आग लगने के समय वह ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन आग लगने के दौरान मरीजों को छोड़कर वहां से चले गए। इतना ही नहीं, सरकारी सेवा में रहते हुए निजी अस्पताल में काम करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप भी उन पर लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और मरीजों के प्रति संवेदनहीनता मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, पटना निर्धारित करेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच भी कराई जाएगी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्पष्ट कहा है कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में तैनात चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों से पूर्ण जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। सरकारी दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उम्मीद छोड़ चुके लोगों को मिला खोया फोन, मुजफ्फरपुर पुलिस ने बरामद कर लौटाए 106 मोबाइल

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मोबाइल खोने या चोरी होने के बाद अधिकांश लोग उसकी वापसी की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस का "ऑपरेशन मुस्कान" ऐसे लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने करीब 35 लाख रुपये मूल्य के 106 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने पुलिस की इस पहल की जमकर सराहना की। मोबाइल मिलने के बाद लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। कल्याणी निवासी मदन कुमार पटेल ने बताया कि मंदिर से घर लौटने के दौरान उचक्कों ने उनका मोबाइल छीन लिया था। घटना के बाद वह काफी परेशान थे और मोबाइल मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे। लेकिन शिकायत के महज 15 दिनों के भीतर पुलिस ने उनका मोबाइल बरामद कर उन्हें सौंप दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल वापस मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए पुलिस का यह प्रयास उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। औराई की रहने वाली आशा कुमारी ने बताया कि उनका मोबाइल 24 फरवरी को चोरी हो गया था। मोबाइल में कई जरूरी दस्तावेज और संपर्क नंबर थे, जिसके कारण वह काफी परेशान थीं। समय बीतने के साथ उन्होंने भी मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी और नया फोन खरीद लिया था। लेकिन करीब चार महीने बाद जब मुजफ्फरपुर पुलिस ने उनका मोबाइल वापस लौटाया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी, पटना से 3 गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना में लोन दिलाने, एटीएम पिन जनरेट कराने, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और रिवॉर्ड प्वाइंट रिडीम कराने के नाम पर लोगों को ठगने वाले साइबर गिरोह का पटना पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। CCSU की साइबर टीम और साइबर थाना की संयुक्त कार्रवाई में दो पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया गया है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि बनकर की ठगीः पुलिस ने यह कार्रवाई नवनीत नगर, रानीपुर मेहंदीगंज और अशोक नगर वार्ड-11, कंकड़बाग इलाके में की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि बनकर लोगों से संपर्क करते थे और उन्हें झांसे में लेकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे।

400 से अधिक शिकायतें मिलींः साइबर DYSP नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि तकनीकी जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर कई शिकायतें दर्ज मिली हैं। इसके अलावा देश के कई राज्यों से 400 से अधिक मामलों की जानकारी सामने आई है। उन्होंने बताया कि जांच में दो अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह एक संगठित साइबर अपराध गिरोह है, जो सुनियोजित तरीके से लोगों को निशाना बनाता था।

नालंदा और पटना के रहने वाले हैं आरोपीः गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौरव राज, सपना कुमारी और निखिल कुमार

देशभर में 400 से ज्यादा शिकायतें मिलीं, छापेमारी जारी

(20 वर्ष) के रूप में हुई है। इनमें गौरव राज और सपना कुमारी नालंदा जिले के हाजीपुर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि निखिल कुमार पटना के कंकड़बाग का निवासी है।

न्यायिक हिरासत में भेजे गएः पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, उनकी निशानदेही पर फरार साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। साइबर थाना की टीम जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की भी जांच कर रही है, ताकि ठगी के नेटवर्क और पीड़ितों की संख्या का पता लगाया जा सके।

सलखुआ में सुइस गेट का डीएम ने किया निरीक्षण जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः आज दिनांक 10 जून 2026 को जिला पदाधिकारी श्री दीपेश कुमार द्वारा सलखुआ प्रखंड अंतर्गत स्थित सुइस गेट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुइस गेट की वर्तमान स्थिति, जल निकासी व्यवस्था एवं संबंधित संरचनाओं का विस्तृत जायजा लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित संबंधित पदाधिकारियों एवं अभियंताओं से सुइस गेट के संचालन, रखरखाव तथा क्षेत्र में जल प्रबंधन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि सुइस गेट का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यक अनुरक्षण कार्य समय पर पूरा किया जाए, ताकि वर्षा ऋतु के दौरान जल निकासी में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र के किसानों एवं आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाया जाए तथा संभावित जलजमाव की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से ही सुनिश्चित की जाएं। इस मौके पर उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार, संबंधित तकनीकी पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बाढ़ में महाने-धारदा नदी पर युद्धस्तर पर बन रहे चेकडैम

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के बाढ़ और फतुहा अनुमंडल में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चेकडैम निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। दो प्रमुख परियोजनाओं पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिनके पूरा होने के बाद हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। बाढ़ अनुमंडल के महाने नदी पर अंदौली चेकडैम का निर्माण जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

करीब 4 करोड़ रुपये की लागत से जयप्रकाश कंस्ट्रक्शन कंपनी (जेपीसी) इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, अंदौली चेकडैम बनने के बाद आसपास के करीब 10 गांवों की 1500 एकड़ से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इससे किसानों की खेती पर निर्भरता बढ़ेगी और फसल उत्पादन में भी सुधार होने की संभावना है। इसके अलावा चेकडैम से जल संचयन बढ़ेगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर में भी सुधार होगा। मानसून को देखते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजना पूरी की जा सके। जेपीसी के अधिकारी सूरज साह ने बताया कि योजना के तहत पहला चेकडैम फतुहा प्रखंड की जैतीया पंचायत में धारदा नदी पर और दूसरा बाढ़ अनुमंडल के अंदौली में महाने नदी पर बनाया जा रहा है।

डीबीटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का हस्तांतरण, लाभार्थियों में खुशी

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता : पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 10 जून 2026 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए मई 2026 माह की पेंशन राशि का अंतरण किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले के विकास भवन स्थित सभागार में उपस्थित लाभार्थियों को दिखाया गया। जिले का मुख्य कार्यक्रम विकास भवन के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित लगभग 100 से अधिक पेंशनधारियों

की उपस्थिति रही। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा संचालित सभी छह प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत उन सभी लाभार्थियों को मई 2026 की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है, जिनका जीवन प्रमाणीकरण 31 मई 2026 तक पूर्ण हो चुका था। उन्होंने बताया कि जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 52,480, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 1,08,272, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 8,938, लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 13,369, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 1,293 तथा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के 13,859 लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई है। इससे वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों को सम्मान एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। जिला पदाधिकारी ने यह भी बताया कि सहरसा जिले में कुल 2,43,967 पेंशनधारियों में से अब तक 1,99,258 लाभार्थियों ने 30 मई 2026 तक अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया है, जबकि 42,881 पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण अभी लंबित है। उन्होंने अपील की कि जिन पेंशनधारियों ने अब तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वे शीघ्र इसे पूरा कर लें, ताकि उन्हें पेंशन की राशि बिना किसी बाधा के समय पर प्राप्त होती रहे।

एलसीटी घाट पर युवक के डूबने की आशंका रुपये के लेन-देन को लेकर था विवाद

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित LCT घाट पर एक 30 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा नदी में डूब गया। युवक की पहचान मैनपुरा महंथा कॉलेज के पास रहने वाले गोपाल कुमार के रूप में हुई है, जो पेशे से ऑटो चालक था। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कुछ युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

रुपए के लेन-देन को लेकर था विवादः मृतक की मां सुनीता देवी ने बताया कि, 'करीब 15 दिन पहले मोहल्ले में रुपये के लेन-देन को लेकर गोपाल के साथ मारपीट की गई थी। उनका आरोप है कि रविवार दोपहर कुछ युवक गोपाल को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। देर शाम जब वे युवक वापस लौटे तो उन्होंने गोपाल के बारे में पूछताछ की। इस पर युवकों ने बताया कि वे लोग उसे काफी देर तक खोजते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद सभी अपने-अपने घर चले गए।

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोपः गोपाल की मां का आरोप है कि उनके बेटे को

जानबूझकर नदी में डुबोकर मार दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन युवकों के साथ गोपाल गया था, उन्हीं पर उन्हें संदेह है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस मामले को केवल डूबने की घटना बताने का प्रयास कर रही है, जबकि परिवार हत्या की आशंका जता रहा है। मां के मुताबिक, 'जब मैं पुलिस के पास गई तो उन्होंने कहा कि कोई पूछे तो सिर्फ कहना है डूब गया है, जबकि मेरे बेटे को डूबाकर मार दिया है।'

24 घंटे बाद भी नहीं मिला शवः घटना के

♦ परिजनों ने कहा- मोहल्ले के युवकों ने डूबाकर मार डाला

24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद गोपाल का शव बरामद नहीं हो सका है। परिजनों का कहना है कि वे लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि जिन लोगों पर उन्हें शक है, वे घटना के समय नशे में थे। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पुलिस कर रही जांचः पाटलिपुत्र SHO अतुलेश कुमार सिंह का कहना है कि नहाने गया था, इसी दौरान डूब गया। मामले की छानबीन की जा रही है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से युवक की तलाश जारी है। शव बरामद होने और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

खुले आसमान के नीचे मेगा स्क्रीन पर देख सकेंगे मूवी

लोकतंत्र की शान , पटना

पटनावासी फ्री में मेगा स्क्रीन पर फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। दरअसल, गांधी मैदान गेट नंबर-4 के पास लगे मेगा स्क्रीन को फिर से शुरू किया जा रहा है। अब हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे से फिल्म दिखाया जाएगा। इस शनिवार और रविवार को पुष्पा फिल्म दिखाई जाएगी। 13 जून को पुष्पा 1 और 14 जून को पुष्पा 2 का दर्शक आनंद ले सकते हैं। फ़िल्मों के अलावा क्रिकेट और कई सांस्कृतिक आयोजनों को भी दिखाया जाएगा।

एक साथ 5,000 दर्शक देख सकते शोः पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इस मेगा स्क्रीन की शुरुआत 2021 में की गई थी। बीच में ये स्क्रीन कई सालों से बंद पड़ी थी। 70 फीट × 40 फीट आकार की यह विशाल स्क्रीन शहर की प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं में से एक

है, जिसे लगभग 70 से 320 फीट की दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता है। लगभग 5,000 लोगों की क्षमता वाली इस व्यवस्था में फुल एचडी पिक्चर, एज-ब्लेंडिंग तकनीक और डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है। पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गांधी मैदान में लगा मेगा स्क्रीन देश का सबसे बड़ा आउटडोर स्क्रीन है, जहां लोग फ्री में फिल्म आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। बडोदरा, मुंबई, दिल्ली आदि में ड्राइव-इन थियेटर हैं, जहां लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर फिल्में देखते हैं।

तेजस्वी का सरकार से सवाल

नौसिखिए मुख्यमंत्री गैर-जरूरी मुद्दों में उलझे, पेंशन के लिए आकस्मिकता निधि से रकम क्यों निकाले?

लोकतंत्र की शान , पटना

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या बिहार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है और क्या डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण राज्य में वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति बनने वाली है।

आकस्मिकता निधि से पेंशन भुगतान पर उठाए सवालः तेजस्वी यादव ने दावा किया कि, 'बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3662 करोड़ निकालने की मंजूरी दी है।'

सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोपः नेता प्रतिपक्ष ने आरोप

लगाया कि, 'पिछले कई महीनों से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान में देरी हो रही है। ठेकेदारों का भुगतान लंबित है, कई स्वीकृत विकास योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है और छात्रवृत्ति व स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं भी प्रभावित हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि फंड की कमी के कारण बिहार राज्य फसल सहायता योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि, 'दशकों से डबल इंजन सरकार होने के बावजूद यदि पेंशन जैसी योजनाओं के लिए आकस्मिकता निधि का सहारा लेना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए।

बिहार में 13 जून तक भारी बारिश की चेतावनी लोगों के मोबाइल फोन पर भेजा गया अलर्ट

लोकतंत्र की शान , पटना

मौसम विभाग ने 13 जून तक बिहार में बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर लोगों के फोन पर वॉर्निंग मैसेज भी भेजा गया है। मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 13 तारीख तक उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। साथ ही, 11 और 12 जून, 2026 को तेज़ हवाओं (50-60 किमी/घंटा) के साथ आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की भी आशंका है। इधर, गर्मी के बीच मुजफ्फरपुर औप मधुबनी में मौसम बदला है। इन दोनों जिलों में दोपहर 3 बजे के बाद बारिश हुई है। खगड़िया में तेज धूप के बाद बादल छाए हैं। सुबह-सुबह बगहा में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24

जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि 9 जिलों में यलो अलर्ट है।

10 जिलों में बारिश, गर्मी से मिली राहतः पिछले 24 घंटे में 10 जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इन जिलों में बेतिया, मोतिहारी, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और मुंगेर में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। बेगूसराय में एक ऑटो के ऊपर पोल गिर गया। ड्राइवर बाल-बाल बच गया।

अगले 5 दिनों में कैसा रहेगा तापमानः मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले पांच दिनों तक बिहार में अधिकतम तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जिन जिलों

♦ मुजफ्फरपुर-मधुबनी में बारिश, खगड़िया में बादल छाए

में बारिश होगी, वहां का तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। जबकि दक्षिण-पश्चिम बिहार के कुछ इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। सप्ताह के अंत तक अधिकांश जिलों में गर्मी से कुछ राहत मिलने के संकेत हैं। राजधानी में आज हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। दिन का तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच रह सकता है। शाम और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहने के आसार है।

संक्षिप्त समाचार

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन का 90% कार्य पूर्ण

सितंबर तक यात्रियों को मिलेगा अत्याधुनिक स्टेशन भवन

लोकतंत्र की शान : एजाज अहमद उस्मानी। मेड़ता रोडः भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। निर्माण कार्य का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है और अब स्टेशन को अंतिम रूप देने का काम जारी है। अधिकारियों के अनुसार सितंबर 2026 तक नया स्टेशन भवन पूरी तरह तैयार कर यात्रियों के लिए खोल दिये जाने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन एक आधुनिक, सुविधायुक्त और तकनीकी रूप से उन्नत स्टेशन के रूप में नई पहचान हासिल करेगा, जिससे न केवल स्थानीय यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी बेहतर यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का होगा विस्तार- पुनर्विकास के तहत स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नए भवन में कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं,

जिनमें शामिल हैं— विस्तृत एवं वातानुकूलित प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना डिस्प्ले बोर्ड, आधुनिक टिकट काउंटर और ऑटोमेटेड सिस्टम, स्वच्छ और सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म,बेहतर प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी, दिव्यांगजन के लिए रैंप और विशेष मार्ग, पेयजल और स्वच्छ शौचालय सुविधाएं, पार्किंग और यातायात प्रबंधन में सुधार

रेलवे प्रशासन का मानना है कि इन सुविधाओं के शुरू होने के बाद यात्रियों को एक बड़े शहर जैसे स्टेशन का अनुभव मिलेगा।

सुरक्षा और संरचना पर विशेष ध्यान- स्टेशन के पुनर्विकास में केवल सौंदर्य ही नहीं, बल्कि सुरक्षा मानकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ प्रबंधन, आग से सुरक्षा के उपाय, आपातकालीन निकास मार्ग और निगरानी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही स्टेशन भवन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यात्रियों की आवाजाही सुगम रहे और किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बनीं जगदंबा सोनी

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

लोकतंत्र की शान सीधी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मध्यप्रदेश की अध्यक्ष एड. अश्विनी परांजपे राजवाड़े ने प्रदेश के नवीन 21 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसमें सीधी जिले की संघर्षशील एवं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता रहीं श्रीमती जगदंबा सोनी को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि श्रीमती जगदंबा सोनी वर्तमान में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ स्वर्णकार समाज की प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ वह वैश्य महासम्मेलन सीधी जिला अध्यक्ष महिला ईकाई के दायित्व का भी निर्वहन कर रही हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा से जगदम्बा सोनी का परिवार जनसंघ के जमाने से जुड़ा है, इनके ससुर स्व. राम निवास सोनी जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। उनकी नियुक्ति पर भारतीय जनता पार्टी सीधी के सभी पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है।

सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री के रूप में देशसेवा करने वाले जननेता बनने पर पीएम मोदी को मुख्यमंत्री ने दी बधाई

लोकतंत्र की शानः लखनऊ। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। गौरतलब है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4399 दिन पूरा कर श्री मोदी सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले जनसेवक बन गए हैं।

145 करोड़ भारतवासियों की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सतत समर्पित हैं प्रधानमंत्री- मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि 145 करोड़ भारतवासियों की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सतत समर्पित, अमृतकाल के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले जननेता बनने पर हार्दिक बधाई। भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है।

युग की चेतना का प्रतीक- मुख्यमंत्री ने लिखा कि इतिहास में ऐसे अवसर विरले ही दिखते हैं, जब कोई नेतृत्व केवल सरकार का नहीं, बल्कि एक युग की चेतना का प्रतीक बन जाता है। यह सम्मान उसी तप, त्याग, दूरदृष्टि और राष्ट्रनिष्ठा का अभिनंदन है, जिसने करोड़ों देशवासियों को 'विकसित भारत' के स्वप्न से जोड़ा है।

प्रधानमंत्री के लिए की मंगलकामना- मुख्यमंत्री ने लिखा कि राष्ट्रसेवा को समर्पित आपकी यह अविराम साधना भारत की प्रगति, प्रतिष्ठा और पराक्रम की नई गाथाएं लिखती रहे, यही मंगलकामना है।

"500 रुपये की मजदूरी और 8 अधजली लाशें... क्या इंसान अब इतना सस्ता हो गया है?"

लोकतंत्र की शान :एजाज़ अहमद उस्मानी की क़लम से

जयपुर के खोह नागोरियान की तंग गलियों में मंगलवार की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी। लोग अपने कामों में लगे थे, बच्चे घरों से निकल रहे थे, और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही पलों बाद हवा में सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि आठ घरों की पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। एक 55 गज के छोटे से मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। कुछ सेकंड... और फिर तेज धमाकों के साथ वहां चीखें गूंजने लगीं। जो बाहर नहीं निकल सके, वे हमेशा के लिए उसी आग में खो गए। दो भाइयों समेत आठ लोगों की मौत ने पूरे इलाके को सुन्न कर दिया।

500 रुपये... और जिंदगी की आखिरी सुबह- कहते हैं कि मजदूरी इंसान को जीने का सहारा देती है, लेकिन यहां वही मजदूरी मौत का सौदा बन गई थी। दिन के सिर्फ 400–500 रुपये... और उसके बदले में बारूद के बीच सांसें गिनते हुए काम।

उन युवाओं को शायद कभी नहीं बताया गया कि जिस काम को वे "रोज़गार" समझ रहे हैं, वह दरअसल एक जिंदा बम के अंदर खड़े होकर काम करने जैसा है। हर दिन खतरे के बीच जीना उनकी मजबूरी थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि एक दिन यह मजबूरी उनकी आखिरी सांस बन जाएगी।

आग नहीं लगी थी... सपने जल रहे थे- हादसे में जान गंवाने वाले लोग सिर्फ नाम नहीं थे। वे किसी के पिता थे, किसी के बेटे, किसी के भाई।

- अब्दुल वाहिद... जो घर का सहारा था।
- बिलाल खान... जिसकी दो छोटी बच्चियां हैं, जो अभी यह भी नहीं जानतीं कि उनका पिता अब कभी घर नहीं लौटेगा।
- समीर... जो कभी सिलाई करता था, लेकिन काम की तलाश उसे मौत के दरवाजे तक ले आई।
- आजीम... जो कुछ महीने पहले ही यहां काम पर लगा था।

हर नाम के पीछे एक अधूरी कहानी है... और हर कहानी के पीछे एक टूटा हुआ घर।

जो रोज लौटते थे, वो अब कभी नहीं लौटेंगे- परिजन बताते हैं कि ये लोग रोज सुबह काम पर जाते थे और शाम को लौट आते थे। घरों में उनका इंतजार होता था। किसी को क्या पता था कि एक दिन वही इंतजार हमेशा के लिए बन जाएगा। मोहल्ले में अब खामोशी है। उन गलियों में जहां कल तक कदमों की आवाजें थीं, वहां अब सिर्फ सिसकियां बची हैं। मांए दरवाजों पर खड़ी हैं, मानो अभी भी कोई आवाज आएगी—"मैं आ गया।" लेकिन अब कोई नहीं आएगा।

एक सवाल जो हर राख से उठ रहा है- सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि आग कैसे लगी... सवाल यह है कि यह फैक्ट्री इतने सालों तक चलती कैसे रही?

55 गज के मकान में बारूद रिफिलिंग होती रही, पटाखे बनते रहे, और दिल्ली तक सप्लाई जाती रही... लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। या फिर सबने देख कर भी आंखें मूंद लीं?

क्या सिस्टम सिर्फ छोटे अपराधों पर ही जागता है? क्या बड़े खतरे तभी दिखते हैं जब लाशें गिननी पड़ती हैं?

घर नहीं जले... परिवार जल गए- यह हादसा सिर्फ एक इमारत का नहीं था। यह आठ परिवारों के सपनों का अंतिम संस्कार था। एक घर जहां सुबह चाय बननी थी, वहां अब चिता की राख है। एक आंगन जहां बच्चों की हंसी गूंजनी थी, वहां अब सन्नाटा है। और एक समाज जो हर बार ऐसे हादसों के बाद कुछ दिन दुख मनाकर फिर भूल जाता है। और अंत में वही दर्दभरा सवाल... क्या सच में एक इंसान की कीमत सिर्फ 500 रुपये रह गई है? या फिर हम सब इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि अब मौतें भी खबर बनकर रह गई हैं... और जिंदगी सिर्फ एक आंकड़ा?

लाखों रुपये की चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लगभग 10 लाख का मशरूका बरामद

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)
लोकतंत्र की शान

सीधी। पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस ने चोरी के एक महत्वपूर्ण प्रकरण का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण एवं नगदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार दिनांक 4 जून 2026 को फरियादी हरीश मिश्र पिता अरुण मिश्रा निवासी डेनिहा थाना कोतवाली जिला सीधी द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अज्ञात चोर द्वारा रात्रि के समय उनके घर का ताला तोडक़र प्रवेश किया गया तथा अलमारी का लॉकर तोडक़र उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण एवं नगद 30 हजार रुपए चोरी कर लिए गए हैं। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंची पुलिस - घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्य एकत्र किए गए। विवेचना के दौरान प्राप्त जानकारी, तकनीकी विश्लेषण एवं मुखबिर सूचना के आधार पर संदेही सुधांशु वर्मा पिता किशन कुमार वर्मा निवासी जोगीपुर की पहचान की गई। पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास करते हुए आरोपी को रायपुर छत्तीसगढ़ से दस्तयाब किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का उपवास, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने का किया विरोध

लोकतंत्र कि शान हसन रशीदः जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर
कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी एवं महिला कांग्रेस के संयुक्त नेतृत्व में जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेसजनों ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर किए गए इस प्रहार के विरुद्ध अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। उपवास कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में जिस प्रकार से झूठ, षड्यंत्र और राजनीतिक दुर्भावना का सहारा लेकर विपक्ष की मजबूत आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, वह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। कांग्रेस पार्टी संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल को समान अवसर मिलना चाहिए। यदि चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर विपक्ष की भागीदारी को बाधित किया जाता है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसी के विरोध में कांग्रेसजनों ने उपवास कर लोकतंत्र एवं संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष सौरभ सिंह, शहर अध्यक्ष एड. अमित शुक्ला, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रजनी वर्मा, राजा जगवानी,विजय पटेल ,राजेश जाटव, जितेन्द्र गुप्ता, अजय जैसवानी, विवेक पांडे, कमल पांडे, मोसुफ अहमद बिट्टू, मंगल सिंह, नारायण निषाद, रंजीत सिंह, श्याम यादव, कल्लू दास बैरागी,विनीत जायसवाल, राजकुमार विश्वकर्मा, सुशील जायसवाल, अजय कोल, सचिन गर्ग,रमेश अहिरवार, दिलदार खान, इमरान खान, मनीष केवट, सोनू चौहान, अर्जुन सिंह, विजय, कल्पना पाठक, रूपा तिवारी, सुमन रजक, दुर्गावती कोल, साहिल, शकील, मनोज वर्मा, समर सिंह एवं हर्षित मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। उपस्थित कांग्रेसजनों ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, संविधान के सम्मान एवं जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

प्रशासन ने जारी किया आदेश, बिना अनुमति रखी गई प्रतिमा

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

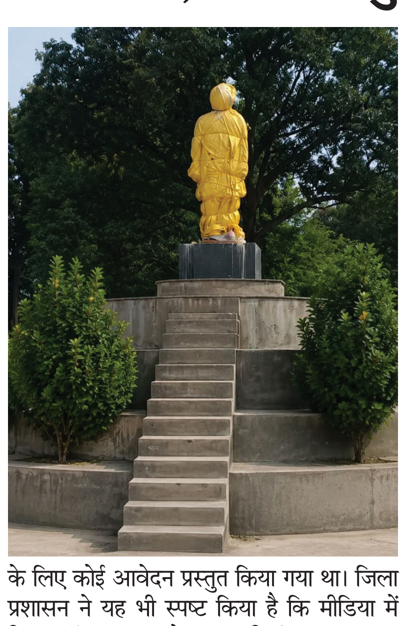

सीधी। लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस सीधी के सामने स्थित चबूतरे प्लेटफार्म पर प्रतिमा स्थापित किए जाने संबंधी मीडिया में प्रकाशित समाचारों के परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन ने तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रतिमा स्थापना संबंधी निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर 2020 में प्रतिमा स्थापना संबंधी नियम एवं प्रक्रियाएं निर्धारित हैं, जिनके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रतिमा स्थापित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना तथा आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य है। प्रकरण की जांच के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी तहसीलदार गोपद बनास एवं लोक निर्माण विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त किए गए। प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस के सामने स्थित शासकीय/नजूल भूमि के एक हिस्से पर नगर पालिका द्वारा शासकीय राशि से चबूतरे का निर्माण कराया गया था। दिनांक 7 जून 2026 की रात्रि लगभग 11 बजे उक्त चबूतरे पर प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रतिमा स्थापना के लिए न तो किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की गई थी और न ही भूमि आवंटन के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिस ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 2 अक्टूबर 2023 का उल्लेख प्रतिमा स्थापना से जोडक़र किया जा रहा है, वह वास्तव में पार्क निर्माण हेतु भूमि आवंटन का आवेदन था। इस संबंध में बताया गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी की अध्यक्षता में आयोजित मॉनिटरिंग सेल की बैठक में रेस्ट हाउस के समीप स्थित शासकीय भूमि को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से पार्क निर्माण कराने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद की पीआईसी बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया तथा पार्क निर्माण हेतु कार्यादेश भी जारी किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि प्रतिमा स्थापना संबंधी किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ तथा इस संबंध में कोई वैधानिक प्रक्रिया प्रचलन में नहीं थी। ऐसे में चबूतरे पर प्रतिमा की स्थापना अनाधिकृत रूप से की गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान स्थिति में प्रतिमा की स्थापना सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है तथा तेज हवा या अन्य परिस्थितियों में सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है तथा मामले में जिम्मेदारी निर्धारित कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने पुनः स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर 2020 में वर्णित प्रावधानों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलए सिविल क्रमांक 8519/2006 में दिनांक 18 जनवरी 2013 को पारित आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा स्थापना संबंधी सभी मामलों में विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन कराया जाएगा।

बारिश में भीगा सरकारी गेहूं, परिवहन व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)
लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं के परिवहन और भंडारण व्यवस्था में लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जिसने सरकारी अनाज की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

बुधवार दोपहर लगभग 3:26 बजे मिनी ट्रक क्रमांक एमपी 53 जीए 6474 में गेहूं लोड कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में लदे गेहूं को बारिश से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे और वाहन पर तिरपाल भी नहीं लगी हुई थी। जानकारी के अनुसार उक्त ट्रक सीधी की ओर से बढ़ौरा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान शहर के समीपी सोनवर्षा टोल प्लाजा के पास अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण ट्रक में लदा बड़ी मात्रा में गेहूं भीग गया। बताया जाता है कि गेहूं पूरी तरह खुले में लोड था, जिसके चलते बारिश का पानी सीधे अनाज पर गिरता रहा। ऐसे में अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने जब वाहन चालक से बात कर यह जानने का प्रयास किया कि बिना तिरपाल लगाए गेहूं का परिवहन क्यों किया जा रहा है, तब चालक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और वाहन लेकर आगे बढ़ गया।

रेत माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा और कसाः घाटों पर उतरी टास्क फोर्स, अवैध रास्तों का नेटवर्क होगा ध्वस्त

कलेक्टर के निर्देश पर बड़वारा-बरही क्षेत्र में बड़ा संयुक्त अभियान, अवैध परिवहन के मार्ग चिन्हित, होंगे ध्वस्त

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ
जबलपुर कटनी

कटनीः जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स ने बड़वारा और बरही क्षेत्र के रेत घाटों में व्यापक संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाकर रेत माफियाओं के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया। कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन के लिए बनाए गए कई अस्थायी मार्गों की पहचान की गई, जिन्हें जल्द ही ध्वस्त कर स्थायी रूप से बंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

नदी किनारों तक पहुंची टीम, खनन क्षेत्रों की हुई बारीक जांच- खनिज विभाग, मध्यप्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने लदहर, सुतरी, बहरघटा, इमलिया, सुड्डी, बसाड़ी, सकरी-कुम्हरवारा सहित विभिन्न स्वीकृत रेत खदानों और घाटों का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने केवल अभिलेखों की जांच तक सीमित न रहकर सीधे नदी तटों पर पहुंचकर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान खदानों में उत्खनन गतिविधियां बंद पाई गईं, लेकिन टीम ने उन स्थानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जहां से अवैध परिवहन की आशंका थी। कई ऐसे कच्चे रास्ते और संपर्क मार्ग चिन्हित किए गए जिनका उपयोग रेत के अवैध परिवहन में किया जा सकता था।

अवैध रास्तों पर चलेगा बुलडोजर- प्रशासन ने रेत माफियाओं द्वारा तैयार किए गए अस्थायी मार्गों की मैपिंग कर उनका पूरा नेटवर्क चिह्नित कर लिया है। पूर्व में तोड़े गए मार्गों का पुनः परीक्षण भी किया गया। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इन रास्तों को पूरी तरह ध्वस्त कर अवैध परिवहन की संभावनाओं को समाप्त किया जाएगा।

नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाईः ऑनलाइन जुए के अड्डे पर दबिश,तीन आरोपी गिरफ्तार, 15 मोबाइल और लैपटॉप जब्त

लोकतंत्र की शानः एजाज़ अहमद उस्मानी

नागौर/मेड़ता रोडः नागौर पुलिस ने ऑनलाइन जुआ संचालित करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, 15 मोबाइल फोन तथा क्रिकेट सट्टेबाजी का हिसाब-किताब रखने वाला रजिस्टर बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर के मार्गदर्शन तथा वृत्ताधिकारी वृत्त नागौर के निकट सुपरविजन में कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना प्रभारी वेदपाल शिवराण के नेतृत्व में टीम द्वारा ऑनलाइन गेम्स की आड़ में चल रही क्रिकेट सट्टेबाजी की सूचना पर कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार डीएसटी टीम को सूचना मिली कि नागौर शहर के मानासर चौराहा क्षेत्र स्थित एक मकान में कुछ युवक क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन जुआ-सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस को मकान के एक कमरे में तीन युवक और एक बालक मौजूद मिले। तलाशी लेने पर वहां से एक लैपटॉप, विभिन्न कंपनियों के 15 मोबाइल फोन तथा क्रिकेट बुकी का हिसाब-किताब दर्ज रजिस्टर बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिकेट मैचों पर सट्टा खिलाने का कार्य कर रहे थे।

पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं एवं आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर ऑनलाइन नेटवर्क और अन्य जुड़े लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है।

गिरफ्तार आरोपी

- राकेश पुत्र रामप्रकाश, निवासी लालाप, थाना भावण्डा, जिला नागौर।
- अशोक पुत्र रतनलाल, निवासी सिणोद, थाना खिवसर, जिला नागौर।
- गजेन्द्र पुत्र महावीर, निवासी सिणोद, थाना खिवसर, जिला नागौर।

बरामदगी

- एक लैपटॉप
- विभिन्न कंपनियों के 15 मोबाइल फोन
- क्रिकेट बुकी का हिसाब-किताब रजिस्टर

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी जैसी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागौर पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

संक्षिप्त समाचार

सूरत में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 4 श्रमिकों की मौत पर एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात के सूरत जिले में एक आभूषण निर्माण इकाई में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान चार श्रमिकों की मौत की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस प्रकरण को मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए गुजरात के मुख्य सचिव और सूरत पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक 7 जून को चार श्रमिक बिना निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किए सेप्टिक टैंक में सफाई के लिए उतरे थे। इस दौरान जहरीली गैसों की चपेट में आने से उनकी हालत बिगड़ गई। बचाव दल द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आयोग ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट की बातें सच हैं तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसलिए आयोग ने गुजरात प्रशासन और पुलिस से घटना की परिस्थितियों, जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया तथा जांच की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। एनएचआरसी ने अपने नोटिस में यह भी कहा कि रिपोर्ट में मृतक श्रमिकों के परिजनों को किसी प्रकार का मुआवजा या अन्य सहायता प्रदान की गई है या नहीं, इसकी जानकारी भी शामिल की जाए। मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक संबंधित आभूषण निर्माण इकाई में आभूषणों की सफाई प्रक्रिया से निकलने वाले अपशिष्ट को एक सेप्टिक टैंक में एकत्र किया जाता था। इसी टैंक की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ।

आईईडी हमले की धमकी, संघ मुख्यालय समेत कई स्थानों पर सुरक्षा कड़ी

नागपुर। नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय सहित कई संवेदनशील स्थानों को आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से निशाना बनाने की धमकी वाला ई-मेल बुधवार को प्राप्त होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। नागपुर और पुणे में संबंधित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 'खालिस्तान' के नाम से भेजा गया यह धमकी भरा ई-मेल संदेश पुणे महापौर कार्यालय के आधिकारिक ई-मेल पते पर प्राप्त हुआ। ई-मेल में पुणे महापौर कार्यालय, नागपुर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर आईईडी हमले की योजना होने का दावा किया गया था। धमकी की सूचना मिलते ही एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। नागपुर के महाल इलाका स्थित संघ मुख्यालय तथा रेशिमबाग स्थित डॉ. हेडगेवार

भवन परिसर में बम खोजी एवं निष्क्रिय दस्ता तैनात किया गया। लगभग 2 घंटे चली गहन जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। ई-मेल में हमले की कोई निश्चित तारीख या समय नहीं बताया गया है। पुलिस, बम निरोधक दस्ता, खुफिया विभाग और साइबर अपराध शाखा के अधिकारियों ने संयुक्त जांच शुरू कर दी है। सतर्कता के रूप में नागपुर स्थित संघ मुख्यालय सहित अन्य संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच, साइबर अपराध जांच दल ने ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी है। ई-मेल रूटिंग, डिजिटल फुटप्रिंट्स और अन्य फोरेंसिक साक्ष्यों का विश्लेषण कर संदेश भेजने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। धमकी वाले ई-मेल में उल्लिखित सभी स्थानों पर युद्धस्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार का विस्फोटक उपकरण, संदिग्ध वस्तु या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है, ऐसा अधिकारियों ने स्पष्ट किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ई-मेल की विस्तृत जांच और फोरेंसिक परीक्षण पूरा होने के बाद ही आगे की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

नेपाल संसद को सुचारू करने के लिए सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के बीच बनी सहमति

काठमांडू। नेपाल के विपक्षी दलों ने बुधवार को सिंहदरबार में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद संसद में लंबे समय से जारी अवरोध समाप्त करने पर सहमति जताई है। यह सहमति कई दिनों से जारी राजनीतिक वार्ताओं के बाद बनी है, जिनका उद्देश्य संसद की कार्यवाही में पैदा हुए गतिरोध को समाप्त करना था। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक निष्कल राई ने बताया कि विपक्षी दलों ने विदेश मंत्री शिशिर खनाल को प्रतिनिधि सभा में संबोधन करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के सीमा मुद्दे पर दिए गए उस विवादित बयान को संसदीय अभिलेख से हटाने के लिए सभामुख से अनुरोध किया जाएगा, जिसने इस विवाद को जन्म दिया था। राई ने कहा कि विपक्षी दल इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संसद की लगातार अवरुद्ध कार्यवाही से जनता के बीच नकारात्मक संदेश जा रहा है। इसी कारण उन्होंने आगे संसद की कार्यवाही में बाधा नहीं डालने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष अपने मुद्दों को उठाता रहेगा और जिन विषयों पर वह लगातार आवाज उठा रहा है, उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। नेपाल-भारत सीमा संबंधी मुद्दों पर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए विपक्षी दलों ने कई दिनों से संसद की कार्यवाही बाधित कर रखी थी, जिसके कारण संसदीय गतिरोध बना हुआ था।

नेपाली पिता-पुत्र ने एक ही सीजन में दो बार एवरेस्ट पर साथ चढ़कर बनाया विश्व रिकॉर्ड

काठमांडू। नेपाल के एक पिता-पुत्र ने पर्वतारोहण के इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए एक ही पर्वतारोहण सीजन के दौरान दो बार साथ मिलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट फतह करने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। पिता-पुत्र की यह उपलब्धि किसी पूर्व नियोजित रिकॉर्ड प्रयास का हिस्सा नहीं थी। दोनों अपने पेशेवर दायित्वों के तहत अभियान मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे थे और इसी दौरान यह ऐतिहासिक कीर्तिमान बन गया। छाङ्वा और लाक्पा तासी शेर्पा ने 17 मई की सुबह 5:30 बजे चीनी पर्वतारोही क्यूलोंग पेंग को समुद्र तल से 8,848.86 मीटर ऊंची एवरेस्ट चोटी तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। अभियान पूरा कर सुरक्षित लौटने के बाद उन्होंने अगले अभियान की तैयारी शुरू कर दी। छह दिन से भी कम समय बाद 23 मई को सुबह 3:29 बजे दोनों पिता-पुत्र एक बार फिर एवरेस्ट के शिखर पर खड़े थे। इस बार वे भारत की प्रतिष्ठित एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो टीम के सदस्यों का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पर्वतारोहण इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। अनुभवी पर्वत मार्गदर्शक छाङ्वा शेर्पा और उनके पुत्र लाक्पा तासी शेर्पा यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले पिता-पुत्र बने हैं। 2026 के पर्वतारोहण सीजन में इस जोड़ी ने मात्र 5 दिन, 21 घंटे और 59 मिनट के अंतराल में दो बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। छाङ्वा शेर्पा वर्ष 2017 से पेशेवर पर्वत मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत हैं और नेपाल के सबसे सफल उच्च हिमालयी गाइडों में गिने जाते हैं। उनके पुत्र लाक्पा तासी बचपन से ही अभियान जीवन को करीब से देखते हुए बड़े हुए। उन्होंने अपने पिता को दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों की ओर जाते देखा और बाद में स्वयं भी इसी पेशे को अपनाने का फैसला किया। लाक्पा तासी के लिए 2026 का सीज़न विशेष रूप से यादगार रहा। इससे पहले वह एवरेस्ट अभियानों में सहयोगी भूमिका निभा चुके थे, लेकिन इस वर्ष उन्होंने पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा। वह भी अपने पिता के साथ। फिर एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार शिखर पर पहुंचकर उन्होंने इस अनुभव को ऐतिहासिक उपलब्धि में बदल दिया। इस सीज़न में दो सफल आरोहण के साथ छाङ्वा शेर्पा ने कुल दसवीं बार एवरेस्ट की चोटी फतह की है। उनका अनुभव केवल एवरेस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने कई अन्य ऊंची हिमालयी चोटियों पर भी सफल अभियान संचालित किए हैं। यह उपलब्धि न केवल नेपाल के पर्वतारोहण इतिहास में बल्कि विश्व पर्वतारोहण समुदाय में भी एक प्रेरणादायक और ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जा रही है।

भारतीय नाविकों के परित्याग पर सख्ती

366 जहाजों पर कार्रवाई, 88 ब्लैकलिस्ट और 278 पर प्रतिबंध

एजेंसी, कोलकाता

देश के नौवहन महानिदेशालय ने भारतीय नाविकों के परित्याग के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए अब तक 88 जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जबकि 278 जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है। कुल मिलाकर 366 जहाजों को परित्याग से जुड़े मामलों में चिह्नित किया गया है। परित्याग की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी नाविक को विदेश के बंदरगाह पर बिना वेतन, भोजन और स्वदेश वापसी की व्यवस्था के छोड़ दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय परिवहन श्रमिक महासंघ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में ही 1,125 भारतीय नाविक ऐसे हालात का शिकार बने, जिससे इस समस्या की गंभीरता उजागर हुई।

नौवहन महानिदेशालय के अनुसार, जिन जहाजों में पहली बार परित्याग की घटना पाई जाती है, उन्हें प्रतिबंधित सूची में रखा जाता है, जबकि दोबारा ऐसी घटना होने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैकलिस्ट किए गए जहाजों पर भारतीय नाविकों की नियुक्ति पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाती है। हाल ही में जारी आदेश में कहा गया है कि परित्याग अंतरराष्ट्रीय समुद्री श्रम मानकों और भारत के समुद्री नौवहन कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। इसमें समुद्री श्रम अभिसमय 2006 के प्रावधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन शामिल है।

आदेश में बताया गया कि नाविकों के स्वदेश वापसी, वेतन भुगतान और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगातार गंभीर कठिनाइयां सामने आई हैं। कई मामलों में जहाज से जुड़े विवरण और वास्तविक जहाज में अंतर पाया गया, जिससे नाविकों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। नौवहन महानिदेशालय ने यह भी कहा कि भर्ती एवं नियुक्ति सेवा लाइसेंस धारक एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। कई एजेंसियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा स्पष्ट किया गया है कि कोई भी लाइसेंसधारी एजेंसी प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट जहाजों पर भारतीय नाविकों की नियुक्ति नहीं कर सकती। ऐसे जहाजों को किसी भी स्थिति में भारतीय नाविकों को काम पर रखने की अनुमति नहीं होगी। महानिदेशालय ने बुधवार सुबह अपने बयान में कहा कि यह कदम भारतीय नाविकों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके वेतन की सुनिश्चितता और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

दो उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

एजेंसी, इंफाल

मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में चंदेल जिले में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। वहीं, इंफाल ईस्ट और टेंग्नौपाल जिलों से दो सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

मणिपुर पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को बताया कि 09 जून को सुरक्षा बलों ने चंदेल जिले के चकपिकारोंग थानांतर्गत आइगेजांग इलाके में अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किया। बरामद सामानों में एक 0.22 राइफल, मैगज़ीन के साथ एक स्थानीय रूप से बनी 9 एमएम पिस्तौल, पांच स्थानीय रूप से बनी सीएमजी, चार स्थानीय रूप से बनी लाथोड गन, 1.2 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और तीन बाओफेंग रेडियो सेट शामिल हैं।

इसी दिन सुरक्षा बलों ने इंफाल ईस्ट जिले के पोरोमपट थानांतर्गत पोरोमपट में जेएनआईएमएस मेन गेट के पास से उग्रवादी संगठन केसीपी (ताइबांगनबा) के एक सक्रिय सदस्य, हाओबिजम हरिदास सिंह उर्फ खोंगनांग (43) (जो वांगू सागांग बाज़ार, बिष्णुपुर जिले का रहने वाला है) को गिरफ़्तार किया।

इसके अलावा, 08 जून को सुरक्षा बलों ने टेंग्नौपाल जिले के मोरेह थानांतर्गत बार्डर पोस्ट (बीपी) 76 इलाके से उग्रवादी संगठन केवाईकेएल के एक सक्रिय सदस्य, खोइराकपाम जेम्स सिंह (28) (जो आंग सेकमाई खुनौ, इंफाल वेस्ट जिले का रहने वाला है) को गिरफ़्तार किया।

पुलिस ने दोनों मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि राज्य में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उग्रवादियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

पूर्व मंत्री उज्ज्वल विश्वास गिरफ्तार, महुआ मोइत्रा ने बताया भाजपा की साजिश

एजेंसी, कृष्णनगर

पश्चिम बंगाल में राहत सामग्री में कथित अनियमितता के मामले में पूर्व कारा मंत्री उज्ज्वल विश्वास को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को उनके आवास के बाहर कथित राहत सामग्री घोटाले को लेकर लोगों का भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने उन पर अंडे भी फेंके। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें मौके से निकालकर हिरासत में लिया और बाद में पूछताछ के उपरांत देर रात गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बुधवार को कृष्णनगर जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।

उज्ज्वल विश्वास की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। कृष्णनगर से तृणमूल कांग्रेस लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को इस कार्रवाई को पूरी तरह राजनीतिक बताते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर साजिश रचने का आरोप लगाया है।

महुआ मोइत्रा ने कहा कि वह स्वयं भी विधायक रह चुकी हैं और राज्य के सभी विधायकों को ईद या अन्य बड़े त्योहारों के अवसर पर वितरण के लिए कपड़े तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता के लिए तिरपाल जैसी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। उनके अनुसार कई विधायक इन सामग्रियों को अपने घरों या गोदामों में रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि उज्ज्वल विश्वास ने भी इन्हें अपने घर में सुरक्षित रखा था।

मप्र के इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन में आए विदेशी प्रतिनिधियों ने किया ग्रामीण हाट का भ्रमण

एजेंसी, इंदौर

मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 से 13 जून तक आयोजित ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण कृषि सम्मेलन में सहभागी बनने आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को इंदौर के प्रसिद्ध ग्रामीण हाट बाजार का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट कृषि उत्पादों, पारंपरिक हस्तशिल्प, प्राकृतिक खेती आधारित उत्पादों तथा एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के अंतर्गत विकसित उत्पादों का अवलोकन किया।

विदेशी प्रतिनिधियों के ग्रामीण हाट आगमन पर उनका मालवा की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप स्वागत किया गया। अतिथियों को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया तथा जनजातीय कलाकारों द्वारा मनमोहक लोक एवं जनजातीय नृत्य प्रस्तुत कर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया गया। जनजातीय कलाकारों के पारंपरिक नृत्य ने विदेशी प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आकर्षित किया। अनेक प्रतिनिधि स्वयं भी नृत्य दल के साथ शामिल हुए और जनजातीय धुनों पर उत्साहपूर्वक झूमते नजर आए।

ग्रामीण हाट में मध्य प्रदेश की कृषि विविधता, स्थानीय उद्यमिता, महिला स्व-सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, मूल्य संवर्धन आधारित कृषि मॉडल तथा प्रदेश की समृद्ध वस्त्र एवं हस्तशिल्प परंपरा को प्रदर्शित किया गया। विदेशी प्रतिनिधियों ने विभिन्न स्टॉलों पर जाकर उत्पादों की जानकारी प्राप्त की तथा उत्पादकों से संवाद भी किया। भ्रमण के दौरान ओडीओपी के अंतर्गत प्रदर्शित बुरहानपुर जिले के केले से निर्मित मूल्य संवर्धित उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। प्रतिनिधियों ने केला चिप्स, केला कुकीज तथा केले के रेशों से निर्मित वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की और कृषि आधारित प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की इस पहल की सराहना की।

बालाघाट जिले के स्टॉल पर प्रदर्शित जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल के साथ-साथ रीवा जिले के जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा एवं अन्य प्रजातियों के आमों ने भी विदेशी मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिनिधियों ने विभिन्न आम प्रजातियों का स्वाद चखा तथा उनकी गुणवत्ता, स्वाद एवं सुगंध की प्रशंसा की। झाबुआ जिले के स्टॉल पर साठी मक्का, दूध मोगर मक्का, देशी उड़द एवं अरहर जैसी पारंपरिक फसलों तथा लंबे रेशों वाले कपास की जानकारी दी गई।

पश्चिम बंगाल में विभागों का बंटवारा- शुभेंदु ने संभाला गृह, भूमि व ऊर्जा, स्वपन दासगुप्ता को वित्त, अग्निमित्रा को शहरी विकास

एजेंसी, भोपाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नई सरकार में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिपरिषद के बीच विभागों का विस्तृत बंटवारा कर दिया है। राज्य सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री ने कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभागों के आवंटन के साथ ही नई सरकार का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग, भूमि एवं भूमि सुधार तथा शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग, विद्युत विभाग, सूचना एवं संस्कृति विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सहित वे सभी विभाग अपने पास रखे हैं, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार की आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण और भूमि संबंधी नीतियों पर मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी रहेगी।

निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास विभाग तथा जल संसाधन जांच एवं विकास विभाग का प्रभार दिया गया है। अशोक कीर्तनिया को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलीप घोष को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विपणन विभाग का मंत्री बनाया गया है। खुदिराम टुडू को जनजातीय विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामले विभाग तथा मदरसा शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया है। अग्निमित्रा पॉल को शहरी विकास एवं नगर मामलों के विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं, दीपक बर्मन को स्कूल शिक्षा विभाग, आवास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं वस्त्र विभाग का प्रभार दिया गया है। तापस राय को उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग, सार्वजनिक उपक्रम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग तथा गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. शंकर घोष को संसदीय कार्य विभाग और पर्यटन विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार उरांव को वन विभाग तथा पर्यावरण विभाग का मंत्री बनाया गया है।

इसके अलावा, अर्जुन सिंह को श्रम विभाग और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। गौरी शंकर घोष को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा जनशिक्षा विस्तार एवं पुस्तकालय सेवा विभाग का प्रभार दिया गया है। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वपन दासगुप्ता को राज्य का वित्त विभाग सौंपा गया है, जिसे सरकार का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विभाग माना जाता है। डॉ. कल्याण चक्रवर्ती को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग का दायित्व दिया गया है।

कैबिनेट ने अमरावती में दो बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को दी मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली

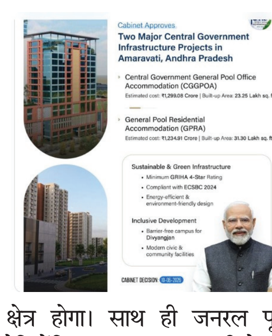

केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में दो प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए जनरल पूल ऑफिस आवास (सीजीजीपीओए) और कर्मचारियों के लिए जनरल पूल रेजिडेंशियल आवास (जीपीआरए) शामिल हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां राष्ट्रीय मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना का विकास करना है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने अमरावती में केंद्रीय सरकारी जनरल पूल ऑफिस आवास परियोजना को 1,299.08 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है। इस परियोजना में 23.25 लाख वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र होगा। साथ ही जनरल पूल रेजिडेंशियल आवास परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 1,234.91 करोड़ रुपये है और इसमें 31.30 लाख वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र होगा।

उन्होंने बताया कि दोनों परियोजनाएं सस्टेनेबल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों पर आधारित होंगी। इनमें न्यूनतम एकीकृत आवास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग (गृहा) 4-स्टार रेटिंग सुनिश्चित की जाएगी और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी 2024) के अनुरूप डिजाइन तैयार किया जाएगा।

भरूच की जामा मस्जिद के तहखाने में हिंदू-जैन देवी-देवताओं की मूर्तियां मिलने का दावा

एजेंसी, भरूच

गुजरात के भरूच जिले में स्थित जामा (जुम्मा) मस्जिद के मूल स्वरूप को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक वीडियो सामने आया है। वीडियो के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के तहखाने में हिंदू-जैन देवी-देवताओं से जुड़ी मूर्तियां मिले हैं।

भरूच के नवचौकी ओवारा स्थित शंकराचार्य मठ के महंत मुक्तानंद स्वामी ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि जामा मस्जिद वास्तव में जैन समरी विहार है। उन्होंने दावा किया कि लंबे आंदोलन और प्रस्तुतियों के बाद जब 700 वर्ष पुराना तहखाना खोला गया, तब वहां से विक्रम संवत 1213 की भगवान मल्लिनाथ की मुर्तियां मिलीं, जो उनके दावे को मजबूत करती हैं। उन्होंने इस स्थल को पुनः मंदिर के रूप में स्थापित करने की मांग की। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रतिबंधित क्षेत्र में बने अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया। साथ ही सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहखाने की ओर जाने वाले एक मुख्य प्रवेश द्वार को फिलहाल स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

विवादित मस्जिद को लेकर हिंदू-जैन पक्ष का कहना है कि 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान मूल जैन समरी विहार मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। उनका दावा है कि मस्जिद के स्तंभों पर आज भी जैन परंपरा की प्राचीन नक्काशी देखी जा सकती है। वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इस स्थल पर सदियों से नियमित रूप से शुक्रवार की नमाज अदा की जाती रही है। जामा मस्जिद के ट्रस्टी अब्दुल कामठी ने कहा कि यह ऐतिहासिक मस्जिद वर्ष 1907 से भारत सरकार के गजट में दर्ज है।

मोदी और नेहरू की तुलना नहीं, यह केवल रिकॉर्ड का विषय : देवेंद्र फडणवीस

एजेंसी, मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच किसी प्रकार की तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह केवल सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने के रिकॉर्ड से जुड़ा विषय है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 27वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर मुंबई स्थित वाय. बी. चव्हाण सेंटर में आयोजित समारोह में वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कहा था कि नेहरू और मोदी की तुलना नहीं की जा सकती। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि, "देश के निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में नेहरूजी के नाम 4,398 दिनों तक पद पर रहने का रिकॉर्ड था, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब 4,399 दिन पूरे कर चुके हैं और आगे भी इस पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार की तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता।"

उन्होंने कहा कि "नेहरू ने अपने समय में जो कार्य किए, उसे देश जानता है और मोदी ने पिछले एक दशक में जो कार्य किए हैं, वे भी सबके सामने हैं। नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए किसी तुलना की आवश्यकता नहीं है।" शरद पवार के बयान पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में फडणवीस ने कहा कि उन्होंने पूरा भाषण नहीं सुना है इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि सिख समुदाय पर कांग्रेस शासनकाल में हुए अत्याचारों की निंदा उनकी पार्टी हमेशा करती रही है और आगे भी करती रहेगी।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार ने हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, "2015 के सूखे के दौरान महाराष्ट्र को विशेष सहायता दी गई। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र की कई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में केंद्र सरकार ने सहयोग दिया। मोदी एक संवेदनशील और जनहित के प्रति समर्पित नेता हैं।"

कांग्रेस की बैठकों और राहुल गांधी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा, "पिछले दस वर्षों से यह दावा किया जाता रहा है कि मोदी सरकार एक वर्ष में चली जाएगी लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी लगातार नए रिकॉर्ड और राजनीतिक सफलताएं हासिल कर रहे हैं। ऐसे दावों को गंभीरता से लेने का कोई कारण नहीं है।"

मोदी युग मे जनविश्वास,सुशासन और विकसित भारत की स्वर्णिम यात्रा

आलेख – विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला'

10 जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिवस के रूप में दर्ज हो गया है,जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक लगातार देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि केवल एक राजनीतिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विश्वास, नेतृत्व की स्वीकार्यता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ जनता ही सर्वोच्च है।यहाँ सत्ता का वास्तविक आधार केवल चुनावी जीत नहीं,बल्कि जनता के मन में स्थापित विश्वास होता है। कोई भी नेता लंबे समय तक जनता का समर्थन तभी प्राप्त कर सकता है जब उसकी नीतियां जनकल्याणकारी हों,उसकी नीयत स्पष्ट हो और उसके निर्णय राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हों।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह ऐतिहासिक उपलब्धि इसी जनविश्वास की कहानी कहती है।

"जब नेतृत्व में नीयत साफ हो।
जब संकल्प राष्ट्रहित का हो॥
तब इतिहास केवल लिखा नहीं जाता।बल्कि नई पीढ़ियों के लिए गढ़ा जाता है।" ॥

एक साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की नरेंद्र मोदी की यात्रा भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और संभावनाओं का जीवंत उदाहरण है।संगठन के एक समर्पित कार्यकर्ता से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री तक का उनका सफर संघर्ष,अनुशासन और निरंतर कर्म की प्रेरक गाथा है।यही कारण है कि देश की जनता ने उन्हें बार-बार अपना विश्वास प्रदान किया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने स्वयं को "प्रधान सेवक" कहा था।उस समय इसे एक राजनीतिक अभिव्यक्ति माना गया था, लेकिन बीते बारह वर्षों में यह शासन की एक कार्यशैली के रूप में उभरकर सामने आई।गरीब,वंचित, किसान, महिला,युवा और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की अवधारणा शासन का प्रमुख आधार बनी।पिछले बारह वर्षों में भारत में कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार अभूतपूर्व स्तर पर देखने को मिला है।करोड़ों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए। गाँव-गाँव तक बिजली पहुंची। उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली।जल जीवन मिशन के जरिए घरों तक नल से जल पहुंचाने का प्रयास किया गया।शौचालय निर्माण अभियान ने ग्रामीण भारत में सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी बदलाव की नई शुरुआत की।

जनधन योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा।प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुँचाया,जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका में कमी आई।मुफ्त राशन योजना ने संकट के समय करोड़ों परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की।आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच उपलब्ध कराया।

"जिस घर में पहली बार उजियारा पहुँचा ।
जिस आंगन में सम्मान का दीप जला ॥वहीं से विकसित भारत का सपना जन-जन के विश्वास में ढलता चला" ॥

गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और आर्थिक अवसरों के विस्तार ने करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई है। यह केवल सरकारी आंकड़ों का विषय नहीं,बल्कि उन परिवारों की वास्तविक कहानी है जिन्होंने पहली बार विकास को अपने जीवन में महसूस किया।

युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हुए सरकार ने कौशल विकास,नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए।आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। डिजिटल भुगतान, फिनटेक और नवाचार के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक पहचान बनाई है।

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।चंद्रयान मिशन की सफलता ने विश्व मंच पर भारत की वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। यह उपलब्धि केवल वैज्ञानिक सफलता नहीं,बल्कि आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी है।

"युवा हाथों में जब नवाचार हो ।
विज्ञान में जब आत्मविश्वास हो ॥
तब चंद्रमा की दूरी भी कम लगती हो।
और भारत विश्व का विश्वास बनता है ॥

महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण आयाम रहा है।उज्ज्वला योजना, मातृत्व लाभ, मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूहों का विस्तार और लखपति दीदी अभियान जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को नए आयाम देने वाला कदम माना जा रहा है।महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की भागीदार बनाने की सोच ने सामाजिक परिवर्तन की नई दिशा दिखाई है।गाँवों से लेकर शहरों तक आज महिलाएं उद्यमिता,शिक्षा, प्रशासन और राजनीति में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की अर्थव्यवस्था का आधार किसान हैं।इसी सोच के साथ किसानों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गईं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार,न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, कृषि तकनीक को बढ़ावा और कृषि निर्यात में वृद्धि जैसे कदमों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है।पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं से जोड़ा गया।कृषि क्षेत्र में विविधीकरण और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया। यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की एक प्रमुख विशेषता बड़े और कठिन निर्णय लेने की क्षमता रही है। ऐसे अनेक विषय,जो दशकों से राजनीतिक चर्चा का हिस्सा थे लेकिन निर्णय की प्रतीक्षा में थे, उन्हें अमल में लाया गया।जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय हो, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करना हो,वन रैंक वन पेंशन योजना हो या तीन तलाक के विरुद्ध कानून—इन सभी ने शासन की निर्णायक शैली को रेखांकित किया।समर्थकों के अनुसार इन फैसलों ने प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे को अधिक प्रभावी बनाया,जबकि आलोचकों ने इनके विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न भी उठाए।किंतु यह निर्विवाद है कि इन निर्णयों ने भारतीय राजनीति में निर्णायक नेतृत्व की एक अलग पहचान बनाई।राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत की नीति में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया।आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई,सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने यह संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा।सीमापार आतंकवाद के विरुद्ध भारत की सक्रिय नीति ने वैश्विक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया।उत्तर-पूर्व में शांति समझौतों, नक्सलवाद के प्रभाव में कमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास ने राष्ट्रीय एकीकरण को नई मजबूती प्रदान की है।

"सीमा सुरक्षित, संकल्प अटल, ।
राष्ट्रहित सर्वोपरि का मंत्र प्रबल।।
शक्ति और शांति का संगम बनकर '
भारत बढ़ रहा है नए संबल के साथ।।"

आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर भारत अभियान ने एक नई सोच को जन्म दिया। कोविड महामारी और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने आत्मनिर्भरता को विकास का आधार बनाने का प्रयास किया। मेक इन इंडिया,उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, सेमीकंडक्टर निर्माण,हरित ऊर्जा और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में निवेश ने देश को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और भारत को उत्पादन,निवेश तथा नवाचार के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।वैश्विक मंचों पर भी भारत की भूमिका पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली हुई है।जी-20 की सफल अध्यक्षता ने भारत की कूटनीतिक क्षमता का परिचय दिया।ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक मंच पर स्थान दिलाने का प्रयास भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका को दर्शाता है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिलना भारतीय सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक है।जलवायु परिवर्तन,सतत विकास और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की पहलें भी विश्व समुदाय में सराही गई हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने केवल विकास की बात नहीं की,बल्कि विकास और विरासत को साथ लेकर चलने का प्रयास किया।नया संसद भवन, कर्तव्य पथ,सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण,तीर्थ स्थलों का विकास और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों का पुनर्स्थापन इसी सोच का हिस्सा हैं।

स्वच्छ भारत अभियान,बेटीबचाओ-बेटी पढ़ाओ,एक पेड़ मां के नाम और जनभागीदारी आधारित अन्य अभियानों ने विकास को केवल सरकारी कार्यक्रम न बनाकर जनआंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया।यही कारण है कि अनेक योजनाओं में समाज की भागीदारी भी दिखाई देती है।सर्वविदित रहे कि बीते बारह वर्षों में राजनीतिक स्थिरता ने भी विकास को नई गति प्रदान की है।सड़क, रेल,मेट्रो,हवाई अड्डों,बंदरगाहों और डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में हुए विस्तार ने भारत के विकास मानचित्र को बदल दिया है। देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक संपर्क और सुविधाओं का विस्तार हुआ है।

"विकास की राह, विरासत का मान,
आत्मनिर्भरता का बढ़ता अभियान।
2047 के स्वर्णिम स्वप्न की ओर,
आगे बढ़ रहा है मेरा महान हिंदुस्तान।"निस्संदेह,10 जून 2026 का यह ऐतिहासिक पड़ाव केवल एक रिकॉर्ड नहीं है।यह उस विश्वास की कहानी है जो जनता ने अपने नेतृत्व में व्यक्त किया है। यह उस लोकतंत्र की कहानी है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता देश का नेतृत्व करते हुए इतिहास रच सकता है।यह उस भारत की कहानी है जो आत्म विश्वास के साथ विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।इतिहास का मूल्यांकन समय करता है,लेकिन वर्तमान का सत्य यह है कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन,आत्मनिर्भरता, वैश्विक प्रतिष्ठा और जनभागीदारी के अनेक नए अध्याय लिखे हैं।आने वाले वर्षों में इन प्रयासों का प्रभाव और अधिक स्पष्ट होगा।जब भारत 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करने की ओर अग्रसर है, तब यह उपलब्धि केवल एक नेता का व्यक्तिगत कीर्तिमान नहीं,बल्कि विकसित भारत के सामूहिक संकल्प की अभिव्यक्ति बनकर सामने आती है।यही कारण है कि 10 जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र, जनविश्वास और राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनकर सदैव स्मरण किया जाएगा।

बेरोजगारों को ठग रहे हैं गिरोहबंद जालसाज

लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल

आजकल ठग बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फर्जी वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं.एक ओर देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती जा रही है और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के दावे खोखले सिद्ध हो रहे हैं। इसीलिए देश के विभिन्न राज्यों से युवा पलायन करके रोजगार की तलाश में दूसरे देशों को जा रहे हैं और जो विदेश जाने का जुगाड़ नहीं कर पाते उनमें से अनेक नौकरी दिलाने का लालच देकर ठगने वाले गिरोहों का शिकार बन रहे हैं। कई बार देश विदेश तक फैले जालसाजों के गिरोह भोले भाले युवाओं को रोजगार दिलाने का झांसा देकर विदेश भेज देते हैं वहां पहुंचने पर पता चलता है कि ठगे गए लेकिन समझौता करना पड़ता है और बेहद निम्न स्तरीय काम रोजगार कर विदेश से लौटने के लिए कई कई साल वहां फंसकर रह जाते हैं। ठगी के कुछ मुख्य प्रचलित तरीके पंजीकरण शुल्क नौकरी शुरू करने या इंटरव्यू के नाम पर एडवांस पैसों की मांग करना.फर्जी जॉइनिंग लेटर बड़ी कंपनियों या सरकारी विभागों के नकली सील-सिक्के वाले पत्र थमाना.वर्क फ्रॉम होम / पार्ट-टाइम टास्कघर बैठे लाइक करें या वीडियो देखें जैसे काम देकर शुरू में थोड़ा फायदा दिखाना और बाद में बड़ी रकम निवेश कराकर ठग लेना। आए दिन इस तरह की वारदातों की झड़ी लगी है युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगी का शिकार बन जाने पर तमाम कैरियर चौपट हो जाता है परिवार की जमा पूंजी ठग लेकर रफूचककर हो जाते हैं इस तरह बेरोजगारों पर दोहरी मार पड़ जाती है। कुछ वारदातों से समझने का प्रयास करें। आपको बता दें कि 2 जनवरी को अनूपशहर (उत्तर प्रदेश) के एक युवक अंकित कुमार को गृह मंत्रालय में डाटा एंट्री आप्रेटर की नौकरी दिलाने का लालच देकर उससे 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में दिल्ली की एक महिला के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। 1 मार्च को नोएडा (उत्तर प्रदेश) में विदेश में ऊंची सैलरी वाली नौकरी दिलवाने का लालच देकर 100 से अधिक लोगों से लगभग 70 लाख रुपयों की ठगी करने वाले 2 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 13 मार्च को गुरुग्राम में वर्क इंडिया ऐप के जरिए शिस कार्पोरेशन नामक फर्जी कम्पनी बनाकर बेरोजगारों से ट्रेनिंग और वैरीफिकेशन के नाम पर पैसे ऐंठने वाले गिरोह के विरुद्ध एफ. आई.आर. दर्ज की गई। 30 मार्च को ठाणे (महाराष्ट्र) में एक बेरोजगार युवक को रूस में अच्छी नौकरी दिलवाने का लालच देकर उससे 2.92 लाख रुपए ठगने के आरोप में एक महिला सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 मई को रायपुर (छत्तीसगढ़) ग्रामीण पुलिस ने सरकारी विभागों में नौकरी दिलवाने के नाम पर 34 लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली करने वाले एक शिक्षक और क्लर्क को गिरफ्तार किया।28 मई को जबलपुर (मध्य प्रदेश) में नौकरी लगवाने का लालच देकर एक युवक से 1.26 लाख रुपए की ठगी मारने का मामला सामने आया। आरोपी स्वयं को नेताओं का करीबी बताकर लोगों से रुपए वसूलता था।3 जून को खटीमा (उत्तराखंड) में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवाने का लालच देकर तथा उसे फर्जी नियुक्तिपत्र देकर उससे 21 लाख रुपए ठग लेने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया 4 जून को पुणे (महाराष्ट्र) के हिंजवाड़ी फेज-2 स्थित थिंक टैक्नोलॉजी इंडिया नाम की कम्पनी द्वारा सैंकड़ों इंजीनियरिंग ग्रैजुएट्स, फ्रैशर्स और इंटर्स को नौकरी, स्टाइपेंड व स्थायी रोजगार का सपना दिखाकर लाखों रुपए ठग लेने के आरोप में कम्पनी के सी.ई.ओ. हर्षल ठाकरे को गिरफ्तार किया गया जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 5 जून को नोएडा (उत्तर प्रदेश) में होटल मैनेजमैंट के छात्रों को विदेशी क्रूज पर नौकरी दिलाने का लालच देकर 52 लाख रुपयों की ठगी करने का भंडाफोड़ हुआ। ठगों ने सोशल मीडिया विज्ञापनों और फर्जी इंटरव्यू के जरिए छात्रों को जाल में फंसाया था। 5 जून को ही सिरसा (हरियाणा) के नाथूसरी चौपटा गांव में अली मोहम्मद नामक युवक को विदेश में नौकरी दिलवाने का लालच देकर उससे 1.90 लाख रुपए ठगने के आरोप में राजस्थान के एक आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया।और अब 6 जून को ग्वालियर (मध्यप्रदेश) के महाराजपुरा में एक तांगा चलाने वाले को नगर निगम में नौकरी दिलवाने का लालच देकर उससे 2.25 लाख रुपए ठग लेने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज किया।

52 वां जी-7 शिखर सम्मेलन फ्रांस 15-17 जून 2026- मोदी -ट्रम्प संभावित मुलाकात से क्या बदल सकता है?-व्यापार, एच -1बी वीजा, टैरिफ और रणनीतिक साझेदारी के नए समीकरण?

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

» जी-7 शिखर सम्मेलन 2026 केवल वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का मंच नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्परिभाषित करने का भी अवसर

» भारतीय पेशेवर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, नवाचार और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए एच -1बी वीजा व्यवस्था को अत्यधिक प्रतिबंधात्मक बनाना दोनों देशों के हित में नहीं होगा -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर फ्रांस के एवियन-ले-बैंस में 52 वां शिखर सम्मेलन 15-17 जून को होने वाले जी-7 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच संभावित द्विपक्षीय बैठक की संभावना प्रबल मानी जा रही है। हालांकि दोनों देशों की ओर से अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार व्यापार, वीजा नीति, ऊर्जा सहयोग और सामरिक साझेदारी जैसे विषय इस मुलाकात के केंद्र में रह सकते हैं।भारत और अमेरिका के संबंध पिछले दो दशकों में निरंतर मजबूत हुए हैं, किंतु 2026 में यह रिश्ता एक नए मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। एक ओर दोनों देश रक्षा, प्रौद्योगिकी इंडो -पैसिफिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं,वहीं दूसरी ओर टैरिफ, व्यापार असंतुलन और आव्रजन नीतियों को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। ऐसे समय में यदि मोदी और ट्रम्प की मुलाकात होती है तो यह केवल एक औपचारिक कूटनीतिक बैठक नहीं होगी, बल्कि आने वाले वर्षों के भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा निर्धारित करने वाली वार्ता भी साबित हो सकती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क्रि वर्तमान परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भारत -अमेरिका व्यापार समझौता है। दोनों देशों के बीच पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से व्यापक व्यापार वार्ताएं चल रही हैं और भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि जुलाई 2026 तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारत का लक्ष्य अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों के लिए अधिक अनुकूल और प्रतिस्पर्धी शुल्क दरें प्राप्त करना है, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए सटीकता से अधिक पहुंच उपलब्ध हो। साथियों, भारत अमेरिका व्यापार के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी टैरिफ नीति है। हाल ही में अमेरिका ने भारत सहित कई देशों के आयात पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि यह कदम श्रम मानकों और व्यापारिक असंतुलन से जुड़े मुद्दों के कारण आवश्यक है,जबकि भारत ने इन आरोपों को खारिज करते

हुए कहा है कि वार्ता के माध्यम से समाधान निकाला जाना चाहिए। यदि जी-7 सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रम्प के बीच सकारात्मक चर्चा होती है तो इन प्रस्तावित टैरिफों में राहत मिलने की संभावना बन सकती है।भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वस्त्र, औषधि, इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के क्षेत्र में भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर हैं। अतिरिक्त शुल्क लागू होने की स्थिति में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। इसलिए नई दिल्ली की प्राथमिकता यह होगी कि किसी भी संभावित व्यापार समझौते में भारतीय उद्योगों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा एच -1बी वीजा है, अमेरिका में काम करने वाले लाखों भारतीय पेशेवरों और आईटी उद्योग के लिए यह विषय अत्यंत संवेदनशील है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा वीजा नियमों को सख्त करने के संकेतों ने भारतीय आईटी कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच चिंता पैदा की है। रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री इस विषय को सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष उठा सकते हैं। भारतीय पक्ष का तर्क है कि भारतीय पेशेवर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, नवाचार और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं,इसलिए एच -1बी वीजा व्यवस्था को अत्यधिक प्रतिबंधात्मक बनाना दोनों देशों के हित में नहीं होगा। एच -1बी केवल रोजगार का विषय नहीं है बल्कि यह भारत- अमेरिका तकनीकी संबंधों की आधारशिला भी है। अमेरिका की प्रमुख तकनीकी कंपनियों में हजारों भारतीय इंजीनियर और विशेषज्ञ कार्यरत हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और सेमी कंडक्टर जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वीजा व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साथियों, ऊर्जा सहयोग भी संभावित वार्ता का प्रमुख विषय माना जा रहा है। अमेरिका पहले ही भारत के लिए तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका हैरिपोर्टों के अनुसार दोनों नेता ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से जुड़े ऊर्जा सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा कर सकते हैं। ऐसे समय में जब वैश्विक ऊर्जा बाजार भू- राजनीतिक तनावों से प्रभावित हैं, भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति पर काम कर रहा है।रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग भी इस मुलाकात का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। चीन के बढ़ते प्रभाव, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रतिस्पर्धा ने भारत और अमेरिका को एक-दूसरे के और निकट लाया है। ट्रम्प प्रशासन भी चीन पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की नीति पर जोर देता रहा है। इस संदर्भ में भारत एक स्वाभाविक साझेदार के रूप में सटीकता से उभरता है। साथियों, हालांकि संबंधों में कुछ राजनीतिक संवेदन शीलताएं भी मौजूद हैं। ट्रम्प द्वारा अतीत में भारत- पाकिस्तान तनाव को लेकर किए गए कुछ दावों को भारत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया था। इसके अतिरिक्त व्यापारिक विवादों और शुल्क संबंधी मतभेदों ने भी दोनों देशों के बीच असहजता पैदा की थी। फिर भी हाल के महीनों में उच्चस्तरीय संपर्कों और कूटनीतिक संवाद ने वातावरण को काफी हद तक सकारात्मक बनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच लगातार वार्ताओं ने यह संकेत दिया है कि दोनों पक्ष मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के इच्छुक हैं।व्यक्तिगत स्तर पर मोदी और ट्रम्प के संबंध भी चर्चा का विषय रहे हैं। दोनों नेताओं ने अपने पिछले कार्यकालों में कई बार सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे की सराहना की है। ट्रम्प ने हाल ही में भी मोदी को अपना "अच्छा मित्र" बताया और भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर आशावाद व्यक्त किया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत समीकरण हमेशा निर्णायक नहीं होते, लेकिन वे कठिन वार्ताओं को आसान बनाने में सहायक अवश्य होते हैं। साथियों, यदि यह बैठक सफल रहती है तो इसके परिणाम कई स्तरों पर दिखाई दे सकते हैं। पहला, व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में गति मिल सकती है। दूसरा, भारतीय पेशेवरों से जुड़े वीजा मुद्दों पर कुछ सकारात्मक संकेत सामने आ सकते हैं। तीसरा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग को नई दिशा मिल सकती है। चौथा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक साझेदारी और अधिक मजबूत हो सकती है। इसके विपरीत यदि टैरिफ और व्यापारिक विवादों पर सहमति नहीं बनती तो संबंधों में तनाव की संभावनाएं भी बनी रह सकती हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क्रि जी-7 शिखर सम्मेलन 2026 केवल वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का मंच नहीं है,बल्कि भारत और अमेरिका के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्परिभाषित करने का भी अवसर है। मोदी-ट्रम्प संभावित मुलाकात से यह स्पष्ट हो सकता है कि आने वाले वर्षों में दोनों देशसहयोग प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक साझेदारी के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करेंगे। वर्तमान संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष मतभेदों के बावजूद संवाद और सहयोग की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए यह मुलाकात केवल दो नेताओं की भेंट नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक साझेदारियों में से एक के भविष्य का संकेतक भी हो सकती है।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

मोदी युग के बारह वर्षः विकास, विश्वास और विराट का उदय

लेखक- ललित गर्ग

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ कालखंड केवल शासन परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण के लिए याद किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते बारह वर्षों का दौर ऐसा ही एक कालखंड है। यह केवल एक प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल की कहानी नहीं है, बल्कि उस भारत की कहानी है जिसने स्वयं को नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नई वैश्विक पहचान के साथ स्वयं को स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि केवल राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि जनता के उस विश्वास का प्रमाण है जो बार-बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त हुआ है। भारत जैसा विशाल, बहुभाषी, बहुधार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरा देश किसी नेतृत्व को लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेश दे, यह अपने आप में असाधारण एवं ऐतिहासिक घटना है। मोदी युग की सबसे बड़ी विशेषता केवल विकास नहीं, बल्कि विकास और विश्वास का समन्वय है। नेहरू युग को आधुनिक भारत के निर्माण का काल कहा गया, तो मोदी युग को उस भारत के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है। मोदी ने केवल सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और डिजिटल नेटवर्क का निर्माण नहीं किया, बल्कि करोड़ों भारतीयों के मन में यह विश्वास भी जगाया कि भारत किसी से कम नहीं है और वह विश्व मंच पर नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। मोदी की सबसे विलक्षण विशेषता यह रही कि उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता संचालन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे जनभावनाओं और राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जोड़ा। वे उन विरले नेताओं में हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं को केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें जनआंदोलन का स्वरूप दिया। स्वच्छ भारत अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सफाई का विषय जो कभी सरकारी विभागों तक सीमित था, उसे राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया। मोदी युग को भारत की गुम होती सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना के लिए भी याद किया जाएगा। सदियों से उपेक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों, तीर्थस्थलों और सांस्कृतिक विरासत को नई गरिमा मिली। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना के सम्मान का प्रतीक बना। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण और सोमनाथ जैसे तीर्थों का विकास यह संकेत देता है कि आधुनिकता और परंपरा एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकती हैं। मोदी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने भारत की विदेश नीति को आत्मविश्वास का नया आयाम दिया। कभी विश्व शक्तियों के बीच संतुलन साधने वाला भारत आज वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने वाला राष्ट्र बनकर उभरा है। रूस-यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिम एशिया का संकट हो, जी-20 का नेतृत्व हो अथवा वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज उठाने का प्रश्न- भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई है। यह वही भारत है जिसे कभी विकासशील देशों की कतार में खड़ा माना जाता था, लेकिन आज दुनिया उसकी ओर समाधान प्रदाता राष्ट्र के रूप में देख रही है। इन बारह वर्षों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि शासन के केंद्र में पहली बार अंतिम व्यक्ति को रखने का गंभीर प्रयास दिखाई दिया। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। शासन की पारदर्शिता बढ़ी और बिचौलियों की भूमिका सीमित हुई। डिजिटल इंडिया अभियान ने तकनीक को केवल महानगरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया।

फीफा वर्ल्ड कप

अर्जेंटीना ने आइसलैंड को 3-0 से हराया

- चोट से उबरने के बाद मेसी का शानदार प्रदर्शन

अलबामा । फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले आखिरी वॉर्म-अप मुकाबले में अर्जेंटीना ने आइसलैंड के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की। चोट से उबरने के बाद मैदान पर लौटे लियोनेल मेसी भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने एक गोल किया। एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलते हुए आइसलैंड ने मैच की शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ मौके भी बनाए। मिकेल एलर्टसन के पास गोल करने का अच्छा अवसर था, लेकिन वह हाथ आए इस मौके को भुनाने में नाकाम रहे। यह मौका बाद में

मैच का अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद अर्जेंटीना ने खेल पर पकड़ बनाई। आठवें मिनट में वैलेंटिन बार्को ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर पहला गोल किया और टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी। पहले हाफ में अर्जेंटीना ने लगातार आइसलैंड की डिफेंस पर दबाव बनाया, लेकिन और गोल नहीं कर सका। हाफ टाइम तक स्कोर 1-0 रहा। दूसरे हाफ में अर्जेंटीना के कोच ने कई बड़े बदलाव किए। एलेक्सिस मैक एलिस्टर, एंजो फर्नांडीज और लुटारो मार्टिनेज को सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतारा गया। इन खिलाड़ियों के आने से टीम का आक्रमण और मजबूत हो गया। हालांकि, इन बदलावों के बावजूद, डिफेंडिंग चैंपियन अभी भी अपने मौकों को भुना नहीं पाए, लेकिन टीम के लिए चंद मिनटों बाद चीजें उस समय बदल गईं जब लियोनेल मेसी मैदान पर उतरे। 38 साल के मेसी ने आते ही अपने खेल से प्रभाव छोड़ना शुरू किया। उन्होंने शानदार पास देकर लुटारो मार्टिनेज को पेनल्टी दिलाई। इसके बाद 72वें मिनट में मेसी ने खुद पेनल्टी किक पर गोल किया और अर्जेंटीना की बढ़त को 2-0 कर दिया। मेस्सी का यह अंतरराष्ट्रीय करियर का 117वां गोल था, जिसने उनकी शानदार फॉर्म को एक बार फिर साबित किया।

भारतीय टीम की बढ़ी मुश्किलें

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या

नई दिल्ली (एजेंसी)। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं। दरअसल, हार्दिक के पैर में निगल (हल्की चोट) है, जिसके कारण उनका वनडे सीरीज में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। आईपीएल 2026 के दौरान पीठ में ऐंठन की वजह से हार्दिक मुंबई इंडियंस की ओर से कुछ मुकाबले खेलते नजर नहीं आए थे। हार्दिक 2 जून से बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में मौजूद थे। माना जा रहा था कि हार्दिक को वनडे सीरीज खेलने के लिए सीओई की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी। हार्दिक सीओई में फिटनेस टेस्ट के दौरान पूरी तरह से फिट नजर आए थे। उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने के साथ-साथ फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया था। हालांकि, यह निगल उन्हें हाल ही में हुआ है, जिसके कारण उनका 13 जून से शुरू हो रही वनडे सीरीज में खेल पाना मुश्किल

नजर आ रहा है। सूत्रों ने 'आईएएनएस' को बताया, 'हार्दिक पांड्या को सीओई ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए हरी झंडी दे दी थी। हालांकि, अब पता चला है कि उनके पैर में हल्की चोट लग गई है और उन्हें रिकवरी में कुछ हफ्ते लगेंगे।

सूत्र ने आगे कहा, 'इसका मतलब है कि वह अब वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएंगे और सीओई में अपने रिहैब पर ध्यान देंगे।' हार्दिक अगर इस सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो यह भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बल्लेबाजी के साथ-साथ हार्दिक गेंदबाजी भी करते हैं। हार्दिक 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम की योजनाओं का अहम हिस्सा हैं।

हार्दिक ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था। इसके बाद से उन्होंने कोई भी एकदिवसीय मुकाबला नहीं खेला है। हार्दिक का यह इंतजार और भी लंबा हो गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज तक फिट हो पाते हैं या नहीं। हार्दिक से पहले विराट कोहली भी हैमस्ट्रिंग की इंजरी के कारण एकदिवसीय सीरीज से बाहर हो चुके हैं। कोहली के स्थान पर यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है।

विमेंस टी20 वर्ल्ड इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत

नई दिल्ली (एजेंसी)। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कई टीमों ने अपने दमदार प्रदर्शन से एकतरफा जीत दर्ज करते हुए रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई है। आइए, टी20 वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीमों के बारे में जानते हैं।

- **114 रन :** विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम पर है, जिसने 21 फरवरी 2023 को पाकिस्तान के विरुद्ध केपटाउन में 114 रन से जीत हासिल की थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट खोकर 213 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान निर्धारित ओवरों में 99/9 का स्कोर ही बना सका।
- **113 रन :** साउथ अफ्रीका ने 28 फरवरी 2020 को कैनबरा में खेले गए मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 113 रन के अंतर से जीत हासिल की थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने सलामी बल्लेबाज लिजेली ली (101) के शतक के दम पर 195/3 का स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद थाईलैंड को 19.1 ओवरों में महज 82 रन पर समेट दिया।
- **102 रन :** इस लिस्ट में न्यूजीलैंड तीसरे पायदान पर है, जिसने 19 फरवरी 2023 को पार्ल में श्रीलंका के विरुद्ध 102 रन से जीत हासिल की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने सूजी बेट्स (56) और अमेलिया केर (66) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 162/3 का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 15.5 ओवरों में महज 60 रन पर सिमट गई।
- **98 रन :** इंग्लैंड ने 26 फरवरी 2020 को थाईलैंड के खिलाफ 98 रन से जीत हासिल की थी। कैनबरा में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने नैट साइवर-ब्रंट (नाबाद 59) और कप्तान हीथर नाइट (नाबाद 108) के बीच अटूट 169 रन की साझेदारी के साथ 176/2 का स्कोर बनाया। इसके जवाब में थाईलैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 78 रन ही बना सकी।

महिला टी20 विश्व कप

ये 5 गेंदबाज कर सकती हैं दमदार प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण का आगाज 12 जून से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाना है। आइए आपको उन पांच गेंदबाजों के नाम बताते हैं, जो इस मेगा इवेंट में अपनी टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं।

- **एनाबेल सदरलैंड :** भले ही सरदलैंड को ऑस्ट्रेलिया की ओर से ज्यादा कामयाबी टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में मिली हो, लेकिन वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भी कारगर साबित हुई है। सदरलैंड का प्रदर्शन पिछले टी20 विश्व कप में कमाल का रहा था। उन्होंने टूर्नामेंट में 15 विकेट चटकाए थे और वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज रही थीं। 26 वर्षीय तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले 85 टी20 मुकाबलों में 53 विकेट निकाल चुकी हैं, जबकि वह बल्ले से भी अहम योगदान दे सकती हैं।
- **चार्ली डीन :** इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाज चार्ली डीन अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को खासा तंग कर सकती हैं। डीन इंग्लैंड की ओर से खेले 51 टी20 मुकाबलों में 67 विकेट निकाल चुकी हैं। इस दौरान उनका इकोनॉमी 6.90 का रहा है। विकेट निकालने के साथ-साथ डीन रनों पर अंकुश लगाने के लिए भी जानी जाती हैं। यही वजह है कि इस विश्व कप में उनका प्रदर्शन इंग्लैंड के लिए काफी मायने रखेगा।
- **दीप्ति शर्मा** भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा बड़े मुकाबलों की खिलाड़ी हैं और अहम मैचों में वह दमदार प्रदर्शन करने की काबिलियत रखती हैं। 144 टी20 मुकाबलों के अपने करियर में वह 64 विकेट निकाल चुकी हैं। दीप्ति बीच के ओवरों में साझेदारी तोड़ने का हुनर बखूबी जानती हैं। दीप्ति अपनी गेंदबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखती हैं। वह बल्ले से भी अहम योगदान दे सकती हैं।
- **अमेलिया केर :** न्यूजीलैंड टीम की कप्तान अमेलिया केर के प्रदर्शन पर इस टी20 विश्व कप में हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं। अमेलिया के लिए यह साल गेंद और बल्ले दोनों से शानदार गुजरा है। वह 11 मुकाबलों में 6.02 की इकोनॉमी से 11 विकेट निकाल चुकी हैं। अपनी घूमती गेंदों के दम पर वह कीवी टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं।
- **शबनम इस्माइल :** रिटायरमेंट से वापस लौटने वालीं शबनम इस्माइल टी20 विश्व कप 2026 में साउथ अफ्रीका के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। इस्माइल अपनी रफ्तार के दम पर बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में खासा तंग करने के लिए जानी जाती हैं। इस्माइल को इंग्लैंड की परिस्थितियों खूब रास आएंगी और रफ्तार के साथ-साथ हवा में स्विंग करती हुई उनकी गेंदें किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकती हैं।

व्यापार

सुंदर पिचाई की नेटवर्थ 1.6 अरब डॉलर

नई दिल्ली, एजेंसी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का आज जन्मदिन है। वह 54 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 10 जून 1972 को हुआ था। भारतीय मूल के पिचाई 2004 में गूगल से जुड़े थे। वह कंपनी में तेजी से आगे बढ़े। 2015 में कंपनी का सीईओ बनने से पहले के 11 सालों में उन्हें चार बार प्रमोशन मिला। हाल ही में अल्फाबेट (गूगल की पैरेंट कंपनी) के बोर्ड ने सुंदर पिचाई के लिए एक नया 3-साल का परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव पैकेज मंजूर किया है। इसके तहत वह अगले 3 सालों में 69.2 करोड़ डॉलर (लगभग 5,700 करोड़ रुपये से अधिक) तक कमा सकते हैं। हालांकि, पिचाई के पैकेज का एक बड़ा हिस्सा 'परफॉर्मेंस स्टॉक

यूनिट्स' के रूप में है। इनकी अंतिम कीमत मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि मूल कंपनी 'अल्फाबेट' शेयरधारकों के लिए कैसा प्रदर्शन करती है। पिछले दशक में सुंदर पिचाई के नेतृत्व में गूगल का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग सात गुना बढ़कर 535 डॉलर अरब से 3.6 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। इस साल जनवरी में इसने कुछ समय के लिए 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा भी पार किया था। फोर्ब्स रियल-टाइम बिलियनेयर्स के अनुसार, 9 जून 2026 तक सुंदर पिचाई की नेटवर्थ 1.6 अरब डॉलर (लगभग 15,265 करोड़)थी। सालों में गूगल की वैल्यूएशन में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी ने पिचाई की निजी संपत्ति को काफी बढ़ाया है। इससे मैकिन्से एंड कंपनी के पूर्व कंसल्टेंट रहे पिचाई अरबपति बन गए हैं। चूंकि उनके नए वेतन-पैकेज का ज्यादा हिस्सा स्टॉक के रूप में है। इसलिए इसे तब तक उनकी नेट वर्थ में नहीं गिना जाएगा जब तक कि यह 'वेस्ट' न हो जाए। इसकी कोई तत्काल या नकद में बदली जा सकने वाली कीमत नहीं होती। आमतौर पर कर्मचारी के कंपनी छोड़ने पर इसे जब्त कर लिया जाता है।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, पिचाई को अभी 20 लाख डॉलर का सालाना वेतन मिलता है। उन्हें आखिरी बार दिसंबर 2022 में 21.80 करोड़ डॉलर का स्टॉक अवॉर्ड मिला था। इसे हालिया वेतन-पैकेज की तरह ही तैयार किया गया था। इन स्टॉक-आधारित अवॉर्ड्स के अलावा, कंपनी की ओर से उनकी निजी सुरक्षा से जुड़े खर्चों को उठाने से भी उनकी कमाई बढ़ती है।

एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा एसबीआई

नईदिल्ली, एजेंसी। अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट आज भी सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी एक ऐसा निवेश है, जहां जोखिम कम होता है और तय ब्याज के साथ नियमित आय की सुविधा मिलती है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। इसके बावजूद देश के बड़े बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक एफडी ब्याज दरें ऑफर कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो यह सामान्य ग्राहकों को 3.05 प्रतिशत से 6.45 प्रतिशत तक और वरिष्ठ नागरिकों को 3.55 प्रतिशत से 6.90 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है। लोकप्रिय अमृत वृष्टि योजना भी निवेशकों के बीच काफी पसंद की जा रही है। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में शामिल अपने ग्राहकों को 2.75 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत तक और वरिष्ठ नागरिकों को 3.25 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है।

सीएमआर ग्रीन आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग, 43 प्रतिशत प्रीमियम पर हुआ डेब्यू

नई दिल्ली, एजेंसी। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज आईपीओ की बुधवार को शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई। कंपनी के शेयरों ने अपने आईपीओ इश्यू प्राइस के मुकाबले 43 प्रतिशत के तगड़े प्रीमियम के साथ बाजार में शुरुआत की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 192 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 275.40 रुपये पर ओपन हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग 268 रुपये पर हुई, जो आईपीओ प्राइस से 40 प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि बाद में निवेशकों ने मुनाफावसूली भी शुरू कर दी, जिससे इसकी कीमत में 8 प्रतिशत से ज्यादा तक की गिरावट आ गई। इस आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और यह कुल 127.07 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसने इसे इस साल के सबसे लोकप्रिय पब्लिक इश्यूज में से एक बना दिया। क्यूआईबी कैटेगरी: संस्थागत निवेशकों ने इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और यह हिस्सा 270.46 गुना भरा। गैर-संस्थागत निवेशकों का सेगमेंट 172.35 गुना बुक हुआ। खुदरा निवेशकों के हिस्से को 27.08 गुना बोलियां मिलीं। धमाकेदार लिस्टिंग के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली भी शुरू कर दी। देखते ही देखते इसमें 8 फीसदी से ज्यादा तक की गिरावट आ गई। 275.40 रुपये के मुकाबले यह शेयर सुबह 10:10 बजे तक 8 फीसदी से ज्यादा गिरकर 251.40 रुपये तक आ गया था।

बनाएंगे भारत का पहला एआई डेटा सेंटर, रिलायंस के शेयर चमके

मुकेश अंबानी और मार्क जुकरबर्ग की नई साझेदारी

नईदिल्ली, एजेंसी। दुनिया के शेयर बाजारों में की वजह से पिछड़ रहे भारत के लिए गुड न्यूज है। मुकेश अंबानी और मार्क जुकरबर्ग की नई साझेदारी से भारत में पहला एआई से लैस डेटा सेंटर स्थापित होने जा रहा है। इस खबर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर शुरुआती कारोबार में ही 1.53 प्रतिशत चढ़कर 1289 रुपये पर पहुंच गए।

सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी ने भारत में अपना पहला एआई से लैस डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है। यह प्रोजेक्ट गुजरात के जामनगर में विकसित की जाएगी और इसे भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कब तक बनकर हो जाएगा तैयार

रिलायंस इंडस्ट्रीज 168 मेगावाट क्षमता वाला अत्याधुनिक डेटा सेंटर विकसित करेगी, जिसे अगले दो वर्षों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। भविष्य में इसकी क्षमता को और बढ़ाने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। मनीकंट्रोल

की खबर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत रिलायंस डेटा सेंटर की डिजाइनिंग, निर्माण, बिजली और यूटिलिटी मैनेजमेंट, रिन्यूअल एनर्जी सप्लाई, नेटवर्क कनेक्टिविटी और मैनेज्ड सर्विसेज जैसी सभी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। यह साझेदारी के बीच पहले से मौजूद रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। दोनों कंपनियां पहले भी भारत और कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एआई आधारित एंटरप्राइज सर्सल्यूशन विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से काम कर चुकी हैं।

मुकेश अंबानी ने क्या कहा

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि यह साझेदारी भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। उन्होंने कहा, मेटा जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए भारत का पहला विशेष एआई डेटा सेंटर बनाना इस बात का प्रमाण है कि भारत वैश्विक एआई क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जामनगर भविष्य में हाइपरस्केल एआई कंप्यूटिंग का प्रमुख केंद्र बनेगा। '

संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि कंपनी भारत में अपना पहला एआई-सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने को लेकर उत्साहित है। उन्होंने कहा, 'जामनगर में बनने वाली यह विश्वस्तरीय सुविधा हमारी वैश्विक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को मजबूत करेगी और भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे दीर्घकालिक निवेश को और गहरा बनाएगी। '

एआई रेस में भारत की बड़ी छलांग

दुनियाभर में एआई तकनीक को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। ऐसे समय में मेटा का भारत में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने का फैसला देश को वैश्विक एआई इकोसिस्टम में मजबूत स्थिति दिला सकता है।विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से न केवल बड़े पैमाने पर निवेश आएगा।

दुबई में घर खरीदना हुआ आसान

नईदिल्ली, एजेंसी। अगर आप यूएई में रहते हैं और दुबई में अपना पहला घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने पहली बार घर खरीदने वालों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसके तहत संपत्ति खरीदना पहले की तुलना में अधिक आसान और किफायती हो गया है।

खबर के मुताबिक दुबई लैंड डिपॉर्टमेंट और अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य यूएई निवासियों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत घर खरीदारों को विशेष छूट, आसान भुगतान विकल्प और बेहतर होम लोन सुविधाएं मिलती हैं।

जुलाई 2025 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 3,200 से अधिक लोगों ने दुबई में अपना पहला घर खरीदा है। इन लेनदेन का कुल मूल्य 5 अरब दिरहम से अधिक बताया गया है।

पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को कई विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे, नई लॉन्च होने वाली परियोजनाओं में प्राथमिकता। ऑफ-प्लान (निर्माणाधीन) प्रॉपर्टी पर विशेष कीमतें, आसान भुगतान योजनाएं, रजिस्ट्रेशन फीस पर ब्याज-मुक्त किस्तों की सुविधा और कम ब्याज दरों पर होम लोन, बैंकों और डेवलपर्स की अतिरिक्त विशेष ऑफर्स। योजना में दुबई

के 22 बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स शामिल हैं। इनमें एमार, नखील, मेरास, डामैक, अजीजी, डेन्यूब, दुबई प्रॉपर्टीज, एलिंगटन, समाना, अराडा और माजिद अल फुत्तैम जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।

योजना में शामिल अमीरात प्रमुख बैंक हैं। ये बैंक विशेष ब्याज दरों और तेज मंजूरी प्रक्रिया के साथ होम फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी।

यूएई का निवासी होना चाहिए। आयु कम से कम 18 वर्ष हो। दुबई में कोई फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति पहले से न हो। खरीदी जाने वाली संपत्ति का मूल्य 50 लाख दिरहम से कम हो। अगर आपके नाम पर पहले से दुबई में कोई फ्रीहोल्ड संपत्ति है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, यदि आपके पास किसी अन्य अमीरात या दुबई के नॉन-फ्रीहोल्ड रिजन में संपत्ति है, तो आप आवेदन कर सकते हैं।

क्या कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा

इस योजना में शामिल होने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। हालांकि, संपत्ति खरीदते समय सामान्य रजिस्ट्रेशन शुल्क और बैंक या डेवलपर द्वारा लागू अन्य शुल्क देय होंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM
किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)